



कमलसन्देश
ikf{kcd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिवशक्ति बक्सी

संपादक मंडल

सत्यपाल
संजीव कुमार सिन्हा

कला संपादक

धर्मेन्द्र कौशल
विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-
त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

l nL; rk : +91(11) 23005798
Oku (dk) : +91(11) 23381428
QDI : +91(11) 23387887

ई-मेल

kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डा. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डा. मुकजी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी-36, एफ.एफ. कॉम्प्लेक्स, झण्डेवाला, नई दिल्ली-55 से मुद्रित करा के, डा. मुकजी स्मृति न्यास, पी.पी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक - प्रभात झा

विषय-सूची



भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 30 सितम्बर एवं 1 अक्टूबर, 2011 को नई दिल्ली में संपन्न हुई।



अध्यक्षीय भाषण.....	7
आर्थिक मुद्दा.....	16
राजनीतिक प्रस्ताव.....	19
भारत-बंगलादेश भूमि समझौते के संबंध में प्रस्ताव.....	24

लेख

यूपीए और लेम्बिंग्स &ykyÑ".k vkMok.kh.....	29
---	----

अन्य

जनचेतना यात्रा.....	26
---------------------	----

भारत के बारे में रोचक तथ्य

- ▶ भारत ने अपने इतिहास में किसी भी देश पर हमला नहीं किया है।
- ▶ जब कई संस्कृतियों में 5000 साल पहले घुमंतू वनवासी थे, तब भारतीयों ने सिंधु घाटी (सिंधु घाटी सभ्यता) में हडप्पा संस्कृति की स्थापना की।
- ▶ भारत का नाम 'इंडिया' इंडस नदी से बना है, जिसके आस-पास की घाटी में आरंभिक सभ्यताएं निवास करती थी। आर्य पूजकों में इस इंडस नदी को सिंधु कहा।
- ▶ ईरान से आए आक्रमणकारियों ने सिंधु को हिंदू की तरह प्रयोग किया। 'हिन्दुस्तान' नाम सिंधु और हिन्दू का संयोजन है, जो कि हिन्दुओं की भूमि के संदर्भ में प्रयुक्त होता है।
- ▶ शतरंज की खोज भारत में की गई थी।
- ▶ बीज गणित, त्रिकोणमिति और कलन का अध्ययन भारत में ही आरंभ हुआ था।
- ▶ स्थान मूल्य प्रणाली और दशमलव प्रणाली का विकास भारत में 100 ई.पू. में हुआ था।
- ▶ भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश तथा प्राचीन सभ्यताओं में से एक है।
- ▶ सांप सीढ़ी का खेल तेरहवीं शताब्दी में कवि संत ज्ञानदेव द्वारा तैयार किया गया था इसे मूल रूप से मोक्षपट कहते थे। इस खेल में सीढ़ियों वरदानों का प्रतिनिधित्व करती थी जबकि सांप अवगुणों को दर्शाते थे। इस खेल को कौड़ियों तथा पांसे के साथ खेला जाता था। आगे चलकर इसे खेल में कई बदलाव किए गए, परन्तु इसका अर्थ वही रहा अर्थात् अच्छे काम लोगों को स्वर्ग की ओर ले जाते हैं जबकि बुरे काम दोबारा जन्म के चक्र में डाल देते हैं।
- ▶ भारत में विश्वभर से सबसे अधिक संख्या में डाकखाने स्थित हैं।
- ▶ भारतीय रेल देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है। यह दस लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है।
- ▶ विश्व का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय 700 ई.पू. में तक्षशीला में स्थापित किया गया था। इसमें 60 से अधिक विषयों में 10500 से अधिक छात्र दुनियाभर से आकर अध्ययन करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय चौथी शताब्दी में स्थापित किया गया था जो शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन भारत का माहनुतम उपलब्धियों में से एक है।

व्यंग्य चित्र



हमें लिखें...

सम्पादक के नाम पत्र

कमल संदेश

सादर आमंत्रित

आपकी राय एवं विचार

सम्पादक,
कमल संदेश

डॉ. मुकजी स्मृति न्यास, पीपी-66
सुब्रह्मण्य भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

ई-मेल:-
kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रिय पाठकगण

कमल संदेश (पाठक) का अंक आपको निम्नलिखित मिल रहा होगा। यदि किसी कारणवश आपको कोई अंक प्राप्त न हो रहा हो तो आप अपने प्रदेश कार्यालय को या हमें अवश्य सूचित करें।
-सम्पादक



अस्थिरता का दौर : अस्थिर यूपीए सरकार

सम्पादकीय

Hkk रत की कांग्रेसनीत यूपीए सरकार का सूत्रधार कौन? जब यह कहा जाता है कि असली प्रधानमंत्री श्रीमती सोनिया गांधी हैं तो न इसका खंडन आता है और न स्वयं वे कुछ कहते हैं जिन्हें कांग्रेस ने कुर्सी की कठपुतली बनाया है। यूपीए सरकार का जनता और आम आदमी से कोई सरोकार नहीं रह गया है। प्रशासन की स्थिति भी इतनी भयावह हो गई है कि यूपीए सरकार के मंत्रीगण अपने-अपने क्षेत्रों में नहीं जा रहे हैं। एकमात्र दादा प्रणब मुकर्जी को छोड़कर नौकरशाह भी किसी को घास नहीं डाल रहे हैं। भारत ने आजादी के बाद अनेक कांग्रेसी सरकारों को केन्द्र में देखा पर कांग्रेस के खुद अनेक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि उन्होंने वर्तमान कांग्रेस नीत यूपीए सरकार का जो हाल देखा है, उससे इतना भी पता नहीं चलता कि ये जीवित हैं या मृत?

भारत सरकार का सारा कार्य ठप पड़ा हुआ है। नौकरशाह अपने-अपने मंत्रालयों की गड़बड़ियों से देश को अवगत कराते हुए उन्हें तिहाड़ भेजने का रोडमैप बना रहे हैं। दशहरा और दीपावली के पावन पर्व जैसे राष्ट्रीय उत्सवों पर यूपीए सरकार के मंत्रियों के चेहरों पर कृत्रिम मुस्कान भी गायब है। अजब सा कोहराम मचा है यूपीए सरकार और कांग्रेस संगठन में।

सवा सौ साल से भी अधिक के इतिहास से जुड़ी कांग्रेस की स्थिति यह है कि अगर उसकी अध्यक्षता बीमार है या उन्हें कैमोथेरेपी के दौर से गुजरना पड़ रहा है तो पूरी की पूरी कांग्रेस कैमोथेरेपी के दौर से गुजर रही है। किसी भी संगठन में जब व्यक्ति आधारित राजनीति शुरू होती है तो स्थिति यही होती है, जो आज कांग्रेस की हुई है और हो रही है।

व्यक्ति आधारित दलों का भविष्य उज्ज्वल नहीं कहा जा सकता। राष्ट्रीय दलों की कमजोरी से उपजे क्षेत्रीय दल और क्षेत्रीय नेताओं की बहुलता ने भी राष्ट्रीय राजनीति को कमजोर किया है। अतः यह कौन नहीं जानता कि क्षेत्रीय दलों के क्षत्रप जिस दिन अलविदा हुए उनका राजनैतिक प्रभाव भी अलविदाई की ओर होगा।

ऐसे माहौल में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वे समझे या न समझे, देश अच्छी तरह जानता है कि यूपीए सरकार की बिदाई अर्थात् एनडीए सरकार के आने की आहट और संकेत पर कोई प्रश्नचिह्न नहीं है। पर देश चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरह आंतरिक कोलाहल में न डूबे। देश यह भी नहीं चाहता कि कोई अराजनैतिक लोग देश चलाएं। देश चाहता है कि सत्ता उनके हाथ में जाए जो मजबूरी में नहीं मजबूती से भारत को चलाएं। ऐसे में भाजपा को अपनी संगठनात्मक शक्ति और कार्य के विस्तार में रात-दिन लग जाना चाहिए। भाजपा देश की उम्मीद है। भाजपा के नेतृत्व और संगठन दोनों को चाहिए कि उनके प्रति जो जन उम्मीद देश में बनी है, वह टूटे नहीं। चुनौतियों को अवसर में बदलने की ताकत बढ़ाने में सभी को एकजुट और सामूहिकता के साथ जुट जाना चाहिए।

जन चेतना यात्रा

देश के पूर्व उप-प्रधानमंत्री और भारतीय राजनीति में बेदाग छवि और राजनीति में स्वच्छ और ईमानदार राजनीतिज्ञ के तौर पर देश में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले लालकृष्ण आडवाणी लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि से "जनचेतना यात्रा" प्रारम्भ कर रहे हैं। उनके मन में है कि राजनीति का रंग बदरंग नहीं होना चाहिए। राजनीति के प्रति देश में उत्पन्न अनास्था समाप्त होनी चाहिए। राजनीति ईमानदारी की होनी चाहिए। राजनीति के व्यावसायीकरण और सुविधाभोगी भाव को समाप्त करने का आह्वान करने और देश के नागरिकों को जगाने, बताने और समझाने का "यात्रा" से अलग कोई रास्ता नहीं हो सकता। पच्चासी वर्ष की उम्र में देश को जगाने का, भारत को झकझोरने का भाजपा का लालकृष्ण आडवाणी के माध्यम से यह प्रयास सराहनीय और साहसिक है। स्वच्छ राजनीति किस तरह की होनी चाहिए, वह बात भी जनता को समझ में आयेगी। लालकृष्ण आडवाणी के इस साहस को सभी को प्रणाम करना चाहिए और इस 'यात्रा' से देश में होने वाले जनजागरण में अपनी-अपनी भागीदारी तय करनी चाहिए।

आडवाणी जी की 'यात्रा' का संदेश भी भाजपा को संपूर्ण भारत में ले जाना चाहिए। साथ ही भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि उनके सबसे बड़े नेता जैसी राजनीति चाहते हैं, कम से कम भाजपा उसी राजनीति की राह पर चलें। ■

भगत सिंह कोश्यारी बने उत्तराखण्ड चुनाव समिति के अध्यक्ष

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने 1 अक्टूबर 2011 को निम्नलिखित चुनावी एवं संगठनात्मक दायित्वों की घोषणा की।

- ▶ उत्तराखण्ड विधानसभा चुनाव की दृष्टि से चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री श्री भगत सिंह कोश्यारी होंगे।
- ▶ पूर्व मुख्यमंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होंगे।
- ▶ पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री श्री श्याम जाजू चंडीगढ़ के नगर निगम चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किये गये।

लेख आमंत्रण

'कमल संदेश' में प्रकाशनार्थ पं. दीनदयाल उपाध्याय के जीवन और कृतित्व पर ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायी लेख आमंत्रित किए जाते हैं। एकात्म मानववाद के प्रणेता एवं हमारे प्रेरणास्रोत पं. दीनदयाल उपाध्याय ने अपना सम्पूर्ण जीवन मां भारती के गौरव और महिमा को बढ़ाने में लगा दिया। हमारा उनके सहयोगियों, सहकर्मियों, शोधकर्तृओं, लेखकों और पत्रकारों से अनुरोध है कि वे 'कमल संदेश' में अपने लेख भेजकर उनकी 'विचार यात्रा' के प्रकाशन में अपना सहयोग दें।

i Hkk r > k | k d n
| E i k n d

शुभ दीपावली





“हम सुशासन के लिए ‘स्वच्छ राजनीति’ के पक्षधर” : नितिन गडकरी

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 30 सितम्बर एवं 1 अक्टूबर, 2011 को नई दिल्ली में संपन्न हुई। इस बैठक में ओजस्वी अध्यक्षीय भाषण देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने देश में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और उनकी सरकार पर जमकर प्रहार किया। श्री गडकरी ने कहा कि जिस तरह एक के बाद एक मंत्री जेल जा रहे हैं उससे लगता है कि कहीं निकट भविष्य में कैबिनेट की बैठक तिहाड़ जेल में न हो और घोटालों में प्रधानमंत्री की भूमिका की जांच करने की जरूरत भी पड़ जाए। श्री गडकरी ने कहा, “हम सुशासन के लिए स्वच्छ राजनीति की राष्ट्रीय आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करने के प्रति संकल्पबद्ध हैं।” हम यहां अध्यक्षीय भाषण का पूर्ण पाठ प्रकाशित कर रहे हैं:—

आदरणीय आडवाणीजी, मंच पर उपस्थित वरिष्ठ सहयोगियों और प्रतिनिधि बंधुओं,

सबसे पहले मैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आप सभी का गर्मजोशी से स्वागत करता हूँ। हम सभी दिल्ली में अक्टूबर 2011 के आरंभ में मिल रहे हैं, इसका भी अपना अलग महत्व है। आज से साठ साल पहले इसी शहर में एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन हुआ था, जिसका एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक सत्ता का उपयोग मातृभूमि के लिए करना था। स्वतंत्रता के उन आरंभिक दिनों में हमारे नवजात लोकतंत्र को एक वास्तविक विकल्प की तलाश थी ताकि कांग्रेस के एकाधिकार को समाप्त किया जा सके। जनसंघ के प्रादुर्भाव से लोकतांत्रिक भारत के राजनीतिक क्षितिज पर एक ऐसी पार्टी उभरी जिसके पास एक उदीयमान नेतृत्व, एक विशिष्ट वैचारिक पहचान और राष्ट्रव्यापी संगठनात्मक नेटवर्क उपलब्ध था। साथियों, हमारे संस्थापक डा. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, पं. दीनदयाल उपाध्याय, और कई अन्य नेताओं ने जो अथक परिश्रम और प्रयास किए, उनके लिए हम उन सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हमने विपक्षी दल के रूप में बेहद अच्छा कार्य किया और लोगों के दिलों को जीता। हमारी प्रगतिशील नीतियों और महत्वपूर्ण

राष्ट्रीय मुद्दों पर साहसिक दृष्टिकोण के साथ-साथ हमारे परिश्रम का हमें बहुत अच्छा प्रतिफल भी मिला और सिर्फ डेढ़ दशक की अल्पावधि में ही हम कई राज्यों में सत्तारूढ़ दल बन गए, जिनमें से अधिकतर में गठबंधन के घटक के रूप में सरकार में शामिल हुए।

हमारे संघर्ष के साठ वर्ष

जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, तो यह जरूर कहना



चाहूंगा कि पिछले साठ सालों में हमने यह साबित किया है कि कोई राजनीतिक दल विशुद्ध राष्ट्रवाद पर आधारित अपनी विचारधारा के बल पर किस तरह से अलग पहचान बना सकता



है। हमने हर संभव तरीके से यह प्रयास किया कि राजनीति सत्ता के खेल के बजाय लोगों की सेवा का सच्चा साधन बने।

मित्रों, इस अवसर पर मैं उन बहुत सारे महान व्यक्तित्वों को भी नमन करता हूँ जो अब हमारे बीच नहीं हैं। डॉ. मुखर्जी, जिन्होंने एक तरह से लकीर खींचने से ही शुरुआत की थी। दीनदयालजी, जिन्होंने हमारे राजनीतिक दर्शन की न केवल नींव रखी, बल्कि संगठनात्मक ढांचा भी स्थापित किया। राजमाता विजयाराजे सिंधिया, जो सारी राजसी सुख-सुविधाएं त्यागकर पार्टी के लिए समर्पित रहीं। यह सूची अनंत है। हम कभी नहीं भूल सकते कि जगन्नाथ राव जोशी, नानाजी देशमुख, सुंदर सिंह भंडारी, कुशाभाऊ ठाकरे भैरोसिंह शेखावत जैसे नेताओं को; और निरसंदेह अटलजी और आडवाणीजी जैसे महान नेताओं को, जिन्होंने हर तरह के संसाधनों की कमी समेत अनगिनत बाधाओं का हिम्मत से मुकाबला किया।

हम इस बात से परिचित हैं कि सत्ता की राजनीति में निःसंदेह इस बात का महत्त्व होता ही है कि सत्ता में कितने समय रहे। हालांकि इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण है आपने शासन कैसा चलाया। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में जब मैं सिंहावलोकन करता हूँ तो महसूस करता हूँ कि हमें कई पहल करने का श्रेय जाता है। राष्ट्र ने अटलजी के रूप में ऐसा पहला विदेश मंत्री पाया, जिन्होंने स्थापित विदेश नीति को जारी रखते हुए उसमें उल्लेखनीय परिवर्तन किए। तीन बार वे प्रधानमंत्री बने और यह सिद्ध कर दिखाया कि गैर-कांग्रेसी दलों की सरकारें भी पूरे कार्यकाल तक सफलतापूर्वक चलाई जा सकती हैं। इसके अलावा अटलजी के नेतृत्व से सफल गठबंधन की राजनीति के युग का सूत्रपात हुआ है। इसी तरह आडवाणीजी ने 'छद्म धर्मनिरपेक्षता' सम्बन्धी ऐसे कई मुद्दों पर गठे, जिन्होंने दो दशकों से भी अधिक समय तक भारतीय राजनीति को प्रभावित किया। 'सबको न्याय, पर तुष्टिकरण किसी का नहीं', जैसे नारे गढ़कर उन्होंने बहुत ही प्रभावशाली तरीके से सभी देशभक्त जनता की पीड़ा एवं आकांक्षाओं को अभिव्यक्त किया।

हम दिल्ली में हैं और यह शहर-राज्य हमेशा जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देता रहा है। मुझे इसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं और हमारे वैचारिक आंदोलन के शुभचिंतकों ने जो मानवीय सेवाएं कीं, उनके चलते ही हम इस क्षेत्र में जमीनी स्तर पर समर्थन हासिल कर पाए हैं। यह दिल्ली ही है जहां पर हम पहली बार अपने स्वयं के बलबूते पर सत्ता

में आये थे।

इस अवसर पर मुझे याद आ रहा है, जब हम इसी साल जनवरी में गुवाहाटी में इकट्ठे हुए थे। हमने तय किया था कि 21 अक्टूबर को जनसंघ का स्थापना दिवस 'कृतज्ञता दिवस' के रूप में मनाएंगे। मैं अपनी सभी राज्य इकाइयों से अनुरोध करता हूँ कि वे अपने उन सभी वरिष्ठ पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति सम्मान और आभार प्रकट करने के लिए सम्मान समारोह आयोजित करें, जो जनसंघ के दिनों से ही सक्रिय हैं और 75 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं।

उद्देश्यपूर्ण राजनीति

यद्यपि भाजपा एक मजबूत लोकपाल की स्थापना के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी, तथापि यह देखकर दुःख होता है कि इतना सब हो जाने के बाद भी यूपीए भ्रष्ट तत्वों को संरक्षण देना जारी रखे हुए है। उल्टे यूपीए ने स्विस बैंक अथवा किन्हीं अन्य विदेशी बैंकों में अवैध रूप से जमा काले धन को वापस देश में लाने के लिए किसी प्रकार की कोई राजनीतिक इच्छा नहीं दर्शाई है। अपनी गलतियों के कारण ही यूपीए का नेतृत्व न केवल अपनी सरकार को नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि समूचे राजनीतिक समुदाय को भी बदनाम कर रहा है।

केंद्र की यूपीए सरकार की तरह, उत्तर प्रदेश में बसपा ने भी पूरी तरह से भ्रष्ट तंत्र कायम कर दिया है। उत्तर प्रदेश इस बात का उदाहरण बन गया है कि बे-रोकटोक भ्रष्टाचार किस तरह से सरकार के बुनियादी दायित्वों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को देखकर पता चलता है कि किस तरह से कांग्रेस और बीएसपी की मिलीभगत चल रही है। यूपीए सरकार करोड़ों रुपए का फंड भेजती है, लेकिन किसी तरह का ऑडिट नहीं करवाती, इस तरह से जनता के धन की दिन-दहाड़े लूट होने दे रही है। बदले में, बसपा केंद्र में यूपीए के भ्रष्टाचार के प्रति नरम रवैया अपनाती है। उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचारियों के गठबंधन का प्रतीक बना हुआ है। मायावती कुशासन, भ्रष्टाचार और लोकतांत्रिक शासन के विनाश का प्रतिनिधित्व करती हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिशों में है। जब-जब यूपीए को केंद्र में समर्थन की जरूरत होती है तो बसपा और सपा तुरंत समर्थन में खड़ी हो जाती हैं और जब वे समर्थन देते हैं तब सीबीआई कहती है मुलायम सिंह और मायावती के विरुद्ध केस में दम नहीं है। हमें इस तिकड़ी से लड़ना है।

भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के हमारे संकल्प में उत्तर प्रदेश शीर्ष प्राथमिकता पर है। हमने उत्तर प्रदेश में कई



घोटाले और स्कैंडल उजागर किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। उ.प्र. के चुनावों की तैयारी करते समय हम गवर्नेंस को फिर से परिभाषित करने और लोगों के मन में फिर से भरोसा पैदा करने का वादा करते हैं।

कांग्रेस के संरक्षण में हो रहे घोटालों की शृंखला में सबसे ताजा उदाहरण गोवा में खनन क्षेत्र में हो रहा भ्रष्टाचार है। गोवा राज्य है तो छोटा सा है, लेकिन उसमें हुआ घोटाला बहुत बड़ा है। समाचारों के अनुसार, गोवा में बारह सौ करोड़ रुपए से लेकर दस हजार करोड़ रुपए तक का अवैध खनन हुआ है। हमें पूरा विश्वास है कि आगामी चुनावों में गोवा के मतदाता इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकेंगे।

मित्रों, देश ने अभी हाल ही में बाबा रामदेव और अण्णा हजारे के नेतृत्व में हुए भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के प्रति व्यापक जनसमर्थन की लहर देखी। गत जून में बाबा रामदेव के नेतृत्व में निर्दोष, शांतिपूर्ण और निहत्थे प्रदर्शनकारियों की जब निर्दयता से पिटाई की गई तब लोगों को आपातकाल की याद ताजा हो आई। उस समय घायल हुई राजबाला की अब आकर हुई मौत इस संघर्ष की पहली शहादत है। कोई भी सम्मानजनक समाज इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लोग तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक राजबाला के हत्यारों को दण्डित नहीं किया जाता। मुझे खुशी है कि प्रमुख विपक्षी दल के रूप में हमने भ्रष्टाचार संबंधी इन मुद्दों को जोरदार ढंग से उठाया। सभी गलत कार्यों विशेषकर 2-जी घोटाले का पर्दाफाश करने में लोकलेखा समिति का योगदान भी महत्वपूर्ण है। जब सरकार इस आन्दोलन से निपटने से विफल रही और गलत प्रकार की कार्रवाई करने के कारण अपने जाल में फंस गई, तो हमारे नेताओं ने गतिरोध को समाप्त करने में मुख्य भूमिका निभाई।

मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार से देश का बड़ा भारी नुकसान होता आया है। भ्रष्टाचार की शुरुआत राजनीति में उद्देश्य के संकट से होती है। लंबे समय से सत्ता में रहने के फायदे उठाने के आदी रहे कांग्रेसी अब सत्ता के बिना रह ही नहीं सकते। सत्ता में बने रहने के लिए वे हर तरह के समझौते करते हैं। भ्रष्टाचार ही इन समझौतों के विषम चक्र का मूल कारण है। हाल ही में, प्राकृतिक संसाधनों की अंधाधुंध लूट यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार का मुख्य तरीका बन गया है। जमीन, पानी और अब एयरवेब की भी भारी लूट की जा रही है। लाइसेंस और परमिट राज वाली अर्थव्यवस्था का मॉडल, 'फूट डालो और राज करो' के सिद्धांत पर आधारित वोट बैंक की राजनीति और व्यक्तिगत संरक्षण के स्तर पर राजनीति की दिनोंदिन गिरावट के चलते कांग्रेसी

कुशासन के हर स्तर पर तीन स्तंभ बन चुके हैं। कुशासन की वजह से ही आतंकवाद को पनपने के लिए उपजाऊ जमीन तैयार होती है। राष्ट्र के सम्मुख खड़ी चुनौतियों का समाधान करने की क्षमता कांग्रेस खो चुकी है। इस प्रक्रिया में, कांग्रेस खुद भी एक समस्या बन चुकी है और उसे चुनावों में पराजित करके हमें इस समस्या का समाधान करना है।

सुशासन और स्वच्छ राजनीति के लिए यात्रा

मुझे प्रसन्नता है कि हमारे वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणीजी की 11 अक्टूबर से लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली, बिहार से शुरु होने जा रही देशव्यापी यात्रा से सुशासन और स्वच्छ राजनीति अब और मुखरता से सार्वजनिक चर्चा का विषय बनेंगे। 11 अक्टूबर यह दिवस लोकनायक जयप्रकाश नारायण, श्री नानाजी देशमुख एवं राजमाता विजया राजे सिंधिया का भी जन्मदिवस है। यहां पर यह भी बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही स्वच्छ राजनीति की समर्थक रही है। हम आडवाणीजी का उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद देते हैं, जिनके चलते भाजपा इस मामले में सबसे भिन्न है कि वही एकमात्र ऐसा दल है, जिसके पास चुनाव प्रचार और पार्टी के अन्य खर्चों के लिए आजीवन सहयोग निधि के रूप में व्यवस्थित मशीनरी है। 50 वर्षों से अधिक के बेदाग चरित्र वाले राजनीतिक नेता के रूप में आडवाणीजी सुशासन और स्वच्छ राजनीति के लिए हमारे संघर्ष को नेतृत्व देने का स्वाभाविक नैतिक अधिकार रखते हैं। हमारी जनचेतना यात्रा प्रशासनिक सुधार, चुनाव सुधार, न्यायिक सुधार और राजनीतिक सुधारों जैसे बहुआयामी सुधारों पर लोगों का ध्यान केंद्रित करेगी।

इसके अलावा, हमारा दल इसका भी पक्षधर रहा है कि राजनीति धन कमाने का जरिया न तो हो सकती है और न ही होनी चाहिए। अनेकों बार हमने अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि वे सुनिश्चित करें कि उनका कामकाज भ्रष्टाचार-मुक्त हो। मुझे इस बात को दोहराते हुए प्रसन्नता हुई है कि हमारी सभी राज्य सरकारें शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता में सुधारने के लिए महत्वपूर्ण उपाय कर रही हैं। हमें इस पर गर्व है कि सबसे पहले मध्य प्रदेश और बिहार में लोकसेवा गारंटी और विशेष न्यायालय अधिनियम बनाए जाने के बाद अन्य राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड और उत्तराखंड भी इसी तरह के कानून बना रहे हैं। इसके अलावा, कई राज्यों में सूचना प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस प्रणालियों के इस्तेमाल से भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि पार्टी ने चुनाव सुधारों को लेकर जो



अध्ययन दल बनाया था, उसने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और हम राजनीति को स्वच्छ बनाने के अपने सम्पूर्ण उद्देश्य को पूरा करने के लिए चुनाव सुधारों पर भाजपा का एजेंडा तैयार करेंगे।

इस अवसर पर मैं यह भी दोहराना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार में शामिल किसी भी व्यक्ति के लिए भाजपा में कोई जगह नहीं है। भ्रष्टाचार के मामले में हम जीरो टॉलरेन्स नीति अपना रहे हैं और आने वाले दिनों में भी हम इस पर कड़ाई से अमल करेंगे। मैं और भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जहाँ तक भारतीय राजनीति में सुधार की बात आती है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता अन्य किसी भी दल की तुलना में कहीं बहुत अधिक है। एन.डी.ए. सरकार के समय गठित न्यायमूर्ति वेंकटचलैया आयोग ने उन सभी तरह के सुधारों पर विचार किया था, जिनके बारे में अब कई सिविल सोसायटी संगठन बात कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि आजकल जिन चुनाव सुधारों की बात हो रही है, उनको देखते हुए वेंकटचलैया आयोग की कुछ प्रमुख सिफारिशों को महत्त्व देने की काफी आवश्यकता है।

राष्ट्रीय परिदृश्य

राष्ट्रीय परिदृश्य में, यूपीए सरकार की छवि सर्वाधिक निम्न स्तर पर पहुँच चुकी है। सरकार में नेतृत्व का गंभीर संकट है। प्रधानमंत्री को अधिकारविहिन बना दिया गया है। मंत्री एक-दूसरे से भिड़े दिखाई दे रहे हैं। एक ही परिवार पर आश्रित रहने के नुकसान भी यूपीए में महसूस किए जाने लगे हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था को नीतियों का संकट बर्बाद कर रहा है। भारत में निवेश के वातावरण पर बुरा असर पड़ रहा है। सरकार किसी तरह के बड़े आर्थिक निर्णय करने में सक्षम नहीं है। लगातार बढ़ती हुई महंगाई, खासतौर पर खाद्य-पदार्थों की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी को बुरी तरह से परेशान कर रखा है। ऐसा लगता है जैसे सरकार ने महंगाई रोकने की अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है और सब कुछ भारतीय रिजर्व बैंक पर छोड़ रखा है। रिजर्व बैंक के पास भी सिर्फ मोनेटरी नीति का औजार है। रिजर्व बैंक ने बीते दिनों में बारह बार ब्याज दरें बढ़ाई हैं, फिर भी मुद्रास्फीति पर कोई असर नहीं पड़ा और वह लगातार बढ़ती जा रही है। ब्याज दरों के बढ़ाने से मकान खरीदने या बनाने के लिए कर्ज लेने वाले मध्यम वर्ग पर असहनीय बोझ पड़ रहा है।

मायूस कर देने वाली मंदी की प्रक्रिया हमारे चेहरों पर दिखने लगी है। हम आर्थिक मंदी और बढ़ती महंगाई के दोहरे और खतरनाक जाल में फंसे जा रहे हैं। ऐसी विकट हालत

में आम आदमी की जेब में पैसा नहीं बचा है, उसे महंगे दाम चुकाने पड़ रहे हैं। देश में निवेश के माहौल पर बुरा असर पड़ रहा है। भ्रष्टाचार से निवेश भी हतोत्साहित हो रहा है। भारत में न केवल वैश्विक निवेश पर असर पड़ा है, बल्कि घरेलू उद्योगों पर भी करारी मार पड़ रही है।

कैश फॉर वोट

‘कैश फॉर वोट कांड’ को उजागर करने वाले हमारे दो पूर्व सांसदों फग्गन सिंह कुलस्ते और महावीर भगोरा सहित सुधीन्द्र कुलकर्णी को अभी हाल ही में गिरफ्तार किया गया है। यह एक बड़ा विचित्र उदाहरण है कि अपराधग्रसित सरकार किस प्रकार हताशा में अपने कुकृत्यों को छिपाने का प्रयास कर रही है। हम एक बार फिर उनकी गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि इस शर्मनाक कांड

मैं यह भी दोहराना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार में शामिल किसी भी व्यक्ति के लिए भाजपा में कोई जगह नहीं है। भ्रष्टाचार के मामले में हम जीरो टॉलरेन्स नीति अपना रहे हैं और आने वाले दिनों में भी हम इस पर कड़ाई से अमल करेंगे।

को संचालित करने वाले असली दोषियों को सामने लाया जाए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। हमें पूरा विश्वास है कि सरकार की ‘कैश फॉर वोट कांड’ की असलियत छिपाने की सारी कोशिशों के बावजूद आखिरकार सत्य की जीत होगी।

आतंकवाद

सरकार की अपरिपक्वता की वजह से शासन में अकर्मण्यता की स्थिति बनती जा रही है। आतंकवाद और अलगाववाद की चुनौतियों की अनदेखी की जा रही है। पिछले कुछ महीनों से आतंकवाद बेलगाम दिखाई देता है। आतंकवादी हमले जारी हैं। हमारी खुफिया एजेंसियों को इन हमले करने वालों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। हमलों के बाद भी हमारी जांच एजेंसियां दोषियों को पकड़ने की कोशिश में हवा में हाथ-पांव चलाती रहती हैं। हाल ही में दिल्ली, मुंबई और कुछ अन्य जगहों पर हुए बम विस्फोट कानून-व्यवस्था की नाकाम मशीनरी की खस्ता हालत बयान कर रहे हैं। इसी तरह, नक्सलवाद के खतरे की भी हम अनदेखी नहीं कर सकते। हमें और भी ज्यादा सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि



नक्सलवादियों ने एनजीओ के रूप में शहरी इलाकों में भी कुछ अड़डे विकसित कर लिए हैं।

कश्मीर के बारे में, कुछ लोग गैर-जिम्मेदाराना तरीके से जनमत संग्रह की बात कर रहे हैं। हम इस तरह के किसी भी कदम का पूरी ताकत से विरोध करते हैं। केंद्र द्वारा नियुक्त वार्ताकारों की बहुचर्चित रिपोर्ट जल्द ही आने वाली है। हम सरकार को पहले से ही चेतावनी देते हैं कि अगर उसने 1953 से पहले की स्थिति बहाल करने की कोई कोशिश की, तो देशभक्त लोग देश भर में इसका विरोध करेंगे और भाजपा इस विरोध का नेतृत्व करेगी।

किसानों की ब्याह

मुझे प्रसन्नता है कि इस साल आप पर्याप्त मानसून की वजह से ऐसी उम्मीद है कि इस बार फिर अच्छी फसल पैदा होगी। हालांकि हम सरकार को सावधान करना चाहते हैं कि नाकाम वितरण व्यवस्था और फसल आने के बाद भंडारण की खराब सुविधाओं से फिर से फसल सड़ सकती है। इस संदर्भ में मैं यह बताना चाहूंगा कि उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में छत्तीसगढ़ और गुजरात की सरकारों की प्रभावशाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए प्रशंसा की है। मैं इन दोनों सरकारों को बधाई देना चाहता हूँ।

आज खाद पिछले वर्ष के मुकाबले 40 प्रतिशत मंहगी हो गई है और इसके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार न तो इसके दामों को नियंत्रित कर रही है और न ही नई खाद फैक्ट्रियों को अनुमति दे रही है। असहाय किसानों को ब्लैकमार्केट से खाद खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। हमें असंगठित क्षेत्र के किसानों की इस परेशानी को मुखरित करना होगा।

जब हम खेती की बात करते हैं, तो इस बात पर आश्चर्य हो सकता है कि हम कब तक कृषि उत्पादों के उचित मूल्यों जैसे पुराने मुद्दों की चर्चा करते रहेंगे। हम सभी जानते हैं कि आंध्र प्रदेश जैसे राज्य में क्या हो रहा है, जहां दुर्भाग्यग्रस्त किसानों ने फसल न उगाने का फैसला किया। किसान ऐसी घोषणा करने पर इसलिए मजबूर हुए, क्योंकि खरीफ की फसल अब फायदेमंद नहीं रह गई है। उत्पादन की लागत उपज से होने वाली आमदनी से भी ज्यादा हो गई है।

याद रहना चाहिए कि ये किसान बारिश या सूखाग्रस्त इलाकों से नहीं हैं। ये किसान पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा और नेल्लौर के भरपूर सिंचाईवाले इलाकों से हैं। अगर यही चलन आगे जारी रहा तो खाद्य सुरक्षा के भविष्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। हम सरकार से मांग करते हैं कि वह तत्काल कदम उठाए और फसल न उगाने की इस स्थिति को खत्म करने के लिए हर संभव कोशिश करे।

आंकड़ों की राजनीति

सच बात तो यह है कि सिर्फ बातें बनाना और कुछ काम न करना यूपीए की पहचान बन गई है। वे बात तो आम आदमी की करते हैं, लेकिन जब गरीबों की परिभाषा की बात आती है तो वे हमेशा गरीबों के हितों के बिल्कुल विपरीत कार्य करते हैं। और अधिक परेशान करनेवाली बात यह है कि आम आदमी का नारा लगाए जाने से यूपीए के नेता ऐसी दुनिया में विचरण करते दिखते हैं, जो हमारे समाज के वंचित तबकों के दुःख-दर्द के प्रति पूरी तरह से संवेदनहीन हैं। यह सब इसलिए हो रहा है, क्योंकि यूपीए सरकार को लगता है कि 32 रुपए और 26 रुपए से ज्यादा कमाने वाले 'अमीर' हैं। यूपीए न केवल गरीब विरोधी है, बल्कि उसके अंदर इतना घमंड भी है कि उसने उच्चतम न्यायालय में शपथ-पत्र देकर एक बार फिर उनका मजाक उड़ाया है।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि गरीब के रूप में पहचान आज शहरों और गांवों में गरीबों के लिए जीवन-मृत्यु का सवाल बन गया है। गरीबी के विविध पहलुओं से बिलकुल बेपरवाह यह सरकार जमीनी वास्तविकता की परवाह किए बिना हर जिले में गरीबों की संख्या बनावटी तरीके से कम दिखाकर आंकड़ों की राजनीति करने में मस्त है। गरीबी रेखा से नीचे वालों को शामिल करने के बजाय यह शामिलों को बाहर करने पर तुली है।

सरकार को यह अहसास हो गया है कि निर्धन वर्ग को गरीबी रेखा से ऊपर नहीं ला सकती, इसलिए वह गरीबी उन्मूलन की नकली संतुष्टि के लिए गरीबी रेखा को नीचे लाने की फालतू कवायद में लग गई है। यह धोखाधड़ी है और भाजपा पूरी ताकत से इसका विरोध करती है। हम इस रवैये की कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से आग्रह करते हैं कि इस तरह के बुनियादी नीतिगत मुद्दों से और अधिक गंभीरता के साथ निपटे। सरकार की गरीबी को सही तरह से परिभाषित करने में असफलता से उन करोड़ों देशवासियों की जिंदगी पर बुरा असर पड़ेगा, जो सब्सिडी वाले अनाज, इंदिरा आवास, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा विकलांगता पेंशन और इसी तरह की कई अन्य योजनाओं के लाभों से वंचित हो जाएंगे। मैं भाजपा-एनडीए शासित सभी राज्यों से आग्रह करता हूँ कि वे केंद्र सरकार के इस रवैये का विरोध करें और गरीबों और वंचित तबकों की भलाई के लिए लड़ें।

हम पहले से कहते आ रहे हैं कि बढ़ती गरीबी, भूख, बेरोजगारी और मूल्य वृद्धि का मूल कारण कांग्रेस की गलत आर्थिक नीतियां और कुशासन है। हर दिन सरकार अपने कदमों से इसे सही सिद्ध करती जा रही है।



गलत परंपरा

साथियों, स्थिति की विडंबना देखिए। एक तरफ तो यह सरकार आत्महत्या करने वालों किसानों के प्रति पूरी तरह से संवेदनहीन दिख रही है, वहीं दूसरी ओर अदालत से सजा पाए अफजल गुरु जैसे अपराधियों की जान बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। भाजपा की स्थिति इस मामले में एकदम साफ है। हमारा मानना है कि जब फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है और भारत के राष्ट्रपति ने दया याचिका खारिज कर दी है तो पूरी तरह से निपट चुके मामले को फिर से शुरू करने की किसी भी कोशिश को कतई सहन नहीं किया जाएगा। अगर इसकी अनुमति दी गई तो राजनीतिक कारणों से बहुत सारे मुकदमों को फिर से शुरू करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हमें गलत परंपराएं नहीं डालनी चाहिए। हम पहले से ही इस प्रवृत्ति का विरोध करते आ रहे हैं और आगे भी ऐसा करते रहेंगे।

साम्प्रदायिक हिंसा विधेयक

हमने अपनी लखनऊ बैठक में साम्प्रदायिक हिंसा विधेयक के बारे में चर्चा की थी। हमारे संसदीय नेताओं और मुख्यमंत्रियों ने राष्ट्रीय एकता परिषद की हाल ही में हुई बैठक में इस विधेयक के बारे में अपना विरोध व्यक्त किया था। अन्य बहुत से पक्षों ने भी ऐसी आशंकाएं व्यक्त की थीं। हम आशा करते हैं कि सरकार को सदबुद्धि आए और यूपीए सरकार इस विधेयक के बारे में दोबारा से सोचे। यदि सरकार इस विधेयक के बारे में आगे कार्रवाई करती है तो मैं यह दोहराना चाहूंगा कि भाजपा हर हाल में इसका विरोध करेगी।

तेलंगाना

कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार सन् 2004 और 2009—दोनों बार आंध्र प्रदेश में तेलंगाना को अलग राज्य बनाने का वादा करके 35 लोकसभा सीटें जीतकर सत्ता में आई। यह उसके चुनाव घोषणा-पत्र में भी था; यूपीए के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में भी था और संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी शामिल था। जब तेलंगाना के करीब 600 युवाओं ने आत्महत्याएं कीं और राज्य की सभी पार्टियों की सर्वदलीय बैठक द्वारा तेलंगाना राज्य की सिफारिश की घोषणा की गई तो उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 दिसंबर, 2009 को तभी तेलंगाना राज्य बनाने का फैसला घोषित किया।

अगले ही दिन सरकार ने संसद के दोनों सदनों को वाहवाही के बीच इसकी सूचना दी। तभी से कांग्रेस सरकार देरी और झूठ का खतरनाक खेल खेल रही है और अपने ही निर्णय पर टिके रहने की अक्षमता या अनिच्छा का प्रदर्शन कर रही है।

इस देरी से तंग आकर तेलंगाना के लोग पूर्ण हड़ताल कर रहे हैं। पिछले लगभग 18 दिनों से क्षेत्र में न तो कोई बस चल रही है, न ट्रेन चल रही है और न ही ऑटो रिक्शे चल रहे हैं। सभी कोयला खदानों में हड़ताल है और बिजलीघर कोयला न मिल पाने की वजह से बंद हो रहे हैं। भारी बिजली कटौती हो रही है। सभी 9 लाख सरकारी

कर्मचारी, शिक्षक, छात्र और यहां तक कि मंदिरों के पुरोहित भी हड़ताल पर हैं।

भाजपा हमेशा से तेलंगाना को राज्य बनाने की प्रबल समर्थक रही है। हमारा दृढ़ विचार है कि आंध्र प्रदेश के बाकी हिस्से के लोगों के साथ किसी भी तरह का अन्याय किए बिना भी तेलंगाना राज्य बनाया जा सकता है। हम एक बार फिर जोरदार मांग करते हैं कि सरकार संसद में तत्काल तेलंगाना का विधेयक लाए। भाजपा तेलंगाना राज्य के लिए अपना पूरा समर्थन दोहराती है। तेलंगाना राज्य का निर्माण ही एकमात्र तरीका है जिससे यह स्थिति समाप्त हो सकती है।

मणिपुर

मित्रों, अब मैं मणिपुर की बिगड़ती स्थिति की चर्चा करना चाहता हूं। करीब दो महीनों से राष्ट्रीय राजमार्गों की कड़ी आर्थिक नाकेबंदी के बाद वहां लोगों को

ब्लैक में आलू 45 से 50 रुपए किलोग्राम, टमाटर तकरीबन 100 रुपए किलोग्राम, प्याज 70 से 90 रुपए किलोग्राम, पेट्रोल 140 रुपए प्रतिलीटर में खरीदना पड़ रहा है। मणिपुर के लोग कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। यह स्थिति सत्तारूढ़ एस.पी.एफ.—कांग्रेस—सी.पी.आई. गठबंधन सरकार के अक्षम नेतृत्व की बनाई हुई है। घमंड और लापरवाही वर्तमान सरकार का अभिन्न गुण बन गया है। भारतीय जनता पार्टी मणिपुर की जनता के साथ पूरी एकजुटता व्यक्त करती है। मणिपुर को बहुत ज्यादा ध्यान, अधिक सहायता देने और अधिक बेहतर शासन की आवश्यकता है। भाजपा राज्य में इस तरह का स्वाभाविक सत्ता-परिवर्तन लाने की दिशा में काम करने का वादा करती है।

हमने अपनी लखनऊ बैठक में साम्प्रदायिक हिंसा विधेयक के बारे में चर्चा की थी। हमारे संसदीय नेताओं और मुख्यमंत्रियों ने राष्ट्रीय एकता परिषद की हाल ही में हुई बैठक में इस विधेयक के बारे में अपना विरोध व्यक्त किया था। अन्य बहुत से पक्षों ने भी ऐसी आशंकाएं व्यक्त की थीं। हम आशा करते हैं कि सरकार को सदबुद्धि आए और यूपीए सरकार इस विधेयक के बारे में दोबारा से सोचे। यदि सरकार इस विधेयक के बारे में आगे कार्रवाई करती है तो मैं यह दोहराना चाहूंगा कि भाजपा हर हाल में इसका विरोध करेगी।

राजस्थान

राजस्थान में स्थिति निरंतर गंभीर होती जा रही है। अशोक गहलोट सरकार अपनी बड़ी राजनीतिक असफलता छिपाने और स्थानीय प्रशासन व कानून-व्यवस्था की मशीनरी को दोष देने की कोशिश कर रही है। इससे लोगों में विश्वास पैदा करने की कोशिश में लगे लोगों का मनोबल कम हुआ है। स्थिति गंभीर बनी हुई है। इस आधार पर हम मांग करते हैं कि इलाके में सद्भाव वापस लाने, सामान्य जन-जीवन बहाल करने और परेशान लोगों का पलायन किसी भी कीमत पर रोकना सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कदम उठाए जाएं। हम राज्य के गृहमंत्री द्वारा दिये गये पूर्णतया गैर जिम्मेदाराना वक्तव्यों के लिए उनकी निंदा करते हैं, क्योंकि यह वक्तव्य जख्मों पर नमक छिड़कने जैसे हैं।

प्राकृतिक आपदाएं

बंधुओं, हम सभी सिक्किम और अन्य राज्यों के कुछ भागों में आए भयानक भूकंप में लोगों के मारे जाने से दुःखी हैं। हालांकि यह संतोष की बात है कि सिक्किम और उत्तरी बंगाल समेत आसपास के कई इलाकों में अनेक भाजपा कार्यकर्ता भूकंप के तुरंत बाद राहत और बचाव कार्यों में जुट गए थे। मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि हमारी राज्य सरकारों ने तत्काल ही सिक्किम को वित्तीय सहायता देने में देर नहीं लगाई। इसके साथ ही, श्री भगत सिंह कोश्यारी के नेतृत्व में भाजपा सांसदों के दल ने स्थिति का जायजा लेने के लिए सिक्किम का दौरा भी किया। हम सिक्किम की जनता के साथ एकजुटता व्यक्त करते हैं। इस प्राकृतिक आपदा ने एक बार फिर से सरहदी इलाकों में हर तरह की संचार सुविधाओं में सुधार की तत्काल आवश्यकता पर ध्यान खींचा है। हम सेना और अर्धसैनिक बलों को इस बात के लिए बधाई देते हैं कि उन्होंने तत्काल ही पीड़ितों को हर संभव सहायता प्रदान की। भूकंप से पीड़ित व्यक्तियों की ही तरह हम अपने देश के कुछ भागों विशेषकर उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश तथा बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ पीड़ितों के बारे में समान रूप से अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। हमारी संबंधित राज्य इकाईयां इन क्षेत्रों में लोगों की सहायता करने का पहले से ही प्रयास कर रहे हैं।

संघीय ढांचे पर चोट

हम सभी जानते हैं कि यूपीए सरकार गुजरात में किस तरह से अस्थिरकरण की राजनीति का खेल, खेल रही है। राज्यपाल के जरिए वहां समानांतर सरकार चलाने के प्रयास हो रहे हैं। गुजरात में राज्य मंत्रिमण्डल की सलाह के बिना राज्य लोकायुक्त की विवादास्पद नियुक्ति इसका ताजा



उदाहरण है। जब हम लखनऊ में मिले थे तो हमने इस बात की समीक्षा की थी कि राजभवनों में कितने सारे विधेयक स्वीकृति के लिए लम्बित पड़े हैं, जो विधानसभाओं से पारित हो चुके हैं। हालत अब और बिगड़ गई है। राज्यपाल के संवैधानिक पद की तरह ही, यह सरकार राजनीतिक उद्देश्यों के लिए सीबीआई का भी इस्तेमाल कर रही है।

हम केन्द्र सरकार द्वारा भाजपा शासित हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्य सरकारों को एनडीए सरकार द्वारा दिए गए 'विशेष आर्थिक सहायता पैकेज' को भी बीच में ही समाप्त करने के निर्णय की भी कड़ी आलोचना करते हैं।

भारत-बंगलादेश संबंध

भाजपा ने भारत के पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने की सभी गंभीर कोशिशों का हमेशा समर्थन किया है। हालांकि, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ताजा बंगलादेश यात्रा के संदर्भ में, हमारा विश्वास है कि पर्याप्त पूर्व तैयारी न किए जाने की वजह से इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में शायद ही कोई मदद मिली है।

यह सच्चाई है कि यूपीए अपने ही सहयोगी दल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तीस्ता जल के मुद्दे पर विश्वास में लेने में असफल रहा है। हालांकि यह इसी वजह से हुआ, क्योंकि पश्चिम बंगाल और सिक्किम के बीच तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे को लेकर समझ विकसित करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के मन में राज्य के उत्तरी हिस्से में सूख रही खेती के प्रति जो चिंता है, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। कुल मिलाकर यह खेद की बात है कि सरकार ने अपनी अपरिपक्वता की वजह से एक बड़ा अवसर हाथ से जाने दिया। असम के बारे में मैं यह दोहराना चाहता हूँ कि वहां के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने भारत-बंगलादेश भूमि-सीमांकन समझौते में असम के हितों के साथ समझौता किया है। राज्य सरकार ने जन भावनाओं की अनदेखी की और कांग्रेस के आलाकमान की धौंस के आगे झुक गई। हाल ही में, हमारी पार्टी की अध्ययन समिति ने भारत-बंगलादेश सीमा का दौरा किया और सीमांत इलाकों में लोगों से अधिकारिक दस्तावेज इकट्ठे किए, जिनसे साबित होता है कि बंगलादेश के लिए जमीन छोड़ी गई है। इस अध्ययन दल की रिपोर्ट राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्तुत की जायेगी।

अफगानिस्तान की स्थिति

दक्षिण एशिया, विशेषकर "अफ-पाक" के नाम से जाने जाने वाले इलाके में भू-राजनीतिक और सुरक्षा की स्थिति अत्यधिक विस्फोटक और खतरनाक बनी हुई है। निश्चित तौर



पर इसका परोक्ष प्रभाव भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ता है। तालिबान-अल कायदा द्वारा अफगानिस्तान में हत्याओं में हाल ही में काफी बढ़ोतरी हुई है। पहले राष्ट्रपति हामिद करजाई के सौतेले भाई की हत्या और अब ताजा आत्मघाती बम विस्फोट, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी की जान चली गई। इन घटनाओं से साबित होता है कि अमेरिका की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इन घटनाओं के बाद राष्ट्रपति ओबामा अफगानिस्तान में इस साल सैनिकों की संख्या कम करने की अपनी योजना के स्तर पर भी फिर से विचार कर सकते हैं ताकि अमेरिका के दूरगामी और वैधानिक क्षेत्रीय हित किसी भी तरह से खतरे में न पड़ें। ऐसे स्वरूप के अफगानिस्तान में भारत और अमेरिका के समान हित हैं, जो लोकतांत्रिक हो, स्थिर हो, आतंकवाद से मुक्त हो और पाकिस्तान के प्रभाव में न हो। ऐसे में सैनिकों की संख्या में कटौती समेत अमेरिका की किसी भी तरह की बदलती

भाजपा भारत-चीन संबंधों में हाल के घटनाक्रमों से चिंतित है। चीन का लद्दाख में लगातार अतिक्रमण और दक्षिण चीन सागर में वियतनाम के साथ भारत के हाल के तेल सौदों पर चीन का नजरिया, दो ऐसे मुद्दे हैं जिनसे बहुत कुशलता से निपटने की आवश्यकता है ताकि किसी भी तरह से भारत के हितों को नुकसान न पहुंचे।

राजनीतिक-राजनयिक और सैन्य रणनीति का तालमेल भारत जैसे उपकारी भागीदार के साथ बनाए रखा जाना चाहिए।

पड़ोस का घटनाक्रम

हमें अमेरिका के पाकिस्तान के साथ राजनीतिक-राजनयिक संबंधों में आए तनाव पर भी ध्यान देना चाहिए। भारत पाकिस्तान में स्थित और वहां से संचालित हो रहे आतंकवादी ढांचे के खतरों की तीव्रता के प्रति अंतरराष्ट्रीय समुदाय को हमेशा विश्वास दिलाने की कोशिश करता रहा है। ऐसा लगता है कि अमेरिका जैसे देश अब आई.एस.आई. और हककानी की कारगुजारियों को समझ गए हैं। इससे आतंक के विरुद्ध लड़ने वाले सभी राष्ट्रों को बल मिलेगा। इसको देखते हुए ताजा घटनाक्रमों के बाद अमेरिका अगर पाकिस्तान से उसके क्षेत्र में अस्थिरताकारी हरकतों के संदर्भ में व्यापक जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग करता है और इसके लिए अमेरिका अगर अपने लिए लाभकारक तरीके लागू करता है तो इसे इस क्षेत्र में अमेरिकी नीति में स्वागत योग्य संशोधन माना जा सकता है। याद रहे, भारत हमेशा से लोकतांत्रिक और स्थिर पाकिस्तान के साथ अच्छे पड़ोसियों के संबंध चाहता रहा है, लेकिन अगर यह सोच लिया जाए कि पाकिस्तान अपने यहां आतंकवादी ढांचे को इसी तरह कायम रखे और आतंकवाद

को पैदा करने, बढ़ावा देने की पाकिस्तान की नीति चलती रहे तब भी हम अपने उदार रवैये पर टिके रहेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता।

भारत के लिए समय आ गया है कि वह पाकिस्तान पर और अधिक अंतरराष्ट्रीय दबाव डलवाए। हमें याद रखना चाहिए कि चीन-पाकिस्तान की स्थापित धुरी के बावजूद चीन भी असहज महसूस कर रहा है। चीन भी इस बात को लेकर चिंतित है कि पाकिस्तान से पैदा हुआ आतंकवाद आगे चलकर उसके कुछ अशांत इलाकों में घुसपैठ कर सकता है। अप्रत्याशित रूप से चीन को कुछ-कुछ गुपचुप तरीके से पाकिस्तान को चेतावनी देनी पड़ी थी कि वह अपनी धरती से चलने वाले आतंकवादी संगठनों और कट्टरपंथी संगठनों पर लगाम कसे। ऐसी स्थिति में बहुत कुछ इस पर

निर्भर करता है कि हम कितनी मुस्तैदी से काम करते हैं और अंतरराष्ट्रीय समुदाय में अपनी स्थिति किस तरह से रखते हैं, ताकि हम सीमापार आतंकवाद के खतरों से निपट सकें।

भाजपा भारत-चीन

संबंधों में हाल के घटनाक्रमों से चिंतित है। चीन का लद्दाख में लगातार अतिक्रमण और दक्षिण चीन सागर में वियतनाम के साथ भारत के हाल के तेल सौदों पर चीन का नजरिया, दो ऐसे मुद्दे हैं जिनसे बहुत कुशलता से निपटने की आवश्यकता है ताकि किसी भी तरह से भारत के हितों को नुकसान न पहुंचे।

कुछ महत्वपूर्ण संगठनात्मक गतिविधियां

अब मैं पिछले दिनों में हुई कुछ महत्वपूर्ण संगठनात्मक गतिविधियों के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं। हमने कुछ प्रकोष्ठों का गठन किया था, वे बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। शिक्षा प्रकोष्ठ, पंचायती राज प्रकोष्ठ, आईटी प्रकोष्ठ, मछुआरा प्रकोष्ठ, निवेशक प्रकोष्ठ, वाणिज्य प्रकोष्ठ, खेल प्रकोष्ठ और सहकारिता प्रकोष्ठ की पिछले चार महीनों में राष्ट्रीय बैठकें हुई हैं। विदेशी मामलों का प्रकोष्ठ, मानवाधिकार प्रकोष्ठ, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ और संचार प्रकोष्ठ भी कई तरह की गतिविधियों में लगे हैं। यह ध्यान देने की बात है कि हमारे गौवंश प्रकोष्ठ ने भाजपा शासित राज्यों के गौ-सेवा आयोगों और मंडलों के अध्यक्षों की बैठक सफलतापूर्वक आयोजित की थी। चिकित्सा प्रकोष्ठ ने हाल ही में अपनी अखिल भारतीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की।



शिल्पकार और जैव-ऊर्जा प्रकोष्ठ भी अपने ढांचे को खड़ा करने में सक्रियता से लगे हैं। हमारे अंत्योदय कार्यक्रम भी अच्छे चल रहे हैं, लेकिन मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि इसमें और अधिक दिलचस्पी से काम करें। हमारे सभी मोर्चे समाज के अपने-अपने तबकों में पार्टी का संदेश पहुंचाने के लिए कई तरह की बहुआयामी गतिविधियां संचालित कर रहे हैं।

आगामी चुनाव

मुझे विश्वास है कि हम सभी 2012 के शुरुआत में अपने सामने आने वाली चुनौतियों से परिचित हैं। उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में हमारे सांगठनिक कौशल की परीक्षा होगी। उत्तराखंड और पंजाब में हमें फिर से जनादेश हासिल करना है, जबकि उत्तर प्रदेश और गोवा में हमें फिर से सत्ता में वापसी करनी है। मणिपुर में भी हमारी इच्छा महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति बनने की है। हमें दिल्ली, मुंबई और कई अन्य नगर निगमों में भी दुबारा लोकप्रिय जनादेश पाने का कठिन काम भी करना है। इन सभी चुनावों में शानदार सफलता के लिए तैयारियां पहले से ही चल रही हैं; लेकिन हम अभी संतुष्ट होकर नहीं बैठ सकते। पार्टी संगठन में स्वस्थ और सद्भावपूर्ण संबंध, जिन राज्यों में हम सत्ता में हैं, वहां विकास और सुशासन के मोर्चे पर हमारी विशिष्ट उपलब्धियां और प्रभावशाली चुनाव-प्रबंधन सफलता पाने के प्रमुख उपाय हैं।

मैं इन राज्यों के अपने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से जोरदार अपील करना चाहता हूँ कि अपने कार्यों से हमारे सांगठनिक आधार को मजबूती प्रदान करना सुनिश्चित करें।

भावी कार्य

मित्रों, हम सुशासन के लिए स्वच्छ राजनीति की राष्ट्रीय आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करने के प्रति संकल्पबद्ध हैं। ऐसा करते समय हमें अपनी सरकारों के अच्छे कार्यों को सामने लाना होगा। आने वाले दिनों में हमारा सुशासन प्रकोष्ठ हमारी सरकारों के विशिष्ट कार्यों के मोनोग्राम की शृंखला जारी करने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से शुरुआत करके इस शृंखला में अहमदाबाद में बस रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण, बंगलुरु में नगरीय प्रशासन में आईटी, और इंदौर में सड़क निर्माण में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप जैसे विषय शामिल रहेंगे।

कांग्रेस के विकल्प के रूप में भाजपा ने यूपीए सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय माहौल बनाने में सफलता पाई है। हम सभी को यह बात दिमाग में रखनी चाहिए कि सरकार की कमियां उजागर करने में हमारी सुनियोजित रणनीति संयुक्त प्रयासों के बल पर और मजबूत की जा सकती है। हमें इस

बात के प्रति सावधान रहना होगा कि हम सभी ने जो सामूहिक रणनीति विकसित की है, उसका इस संदर्भ में क्रियान्वयन हो। हम सभी को सतर्क रहना होगा कि हमारी कथनी और करनी पर लोगों की गहरी निगाह बनी हुई है और हमें किसी भी तरह का विवाद पैदा नहीं होने देना है।

वर्ष 2011 का कुछ ऐतिहासिक महत्व भी है। ठीक सौ साल पहले, 'फूट डालो और राज करो' की नीति पर अमल करनेवाली औपनिवेशिक शक्तियों को बंगाल के विभाजन के फंसले को हमारी मजबूत सांस्कृतिक एकता के कारण वापस लेना पड़ा था। इसी साल लोकमान्य तिलक ने 'गीता रहस्य' जैसी उत्कृष्ट कृति की रचना की थी। इन दोनों घटनाओं का भारत के सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मिक लोकतंत्र और स्थायी बहुलतावाद के ताजा इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान है। साथियों, हमें महान् धरोहर विरासत में मिली है और इस समृद्ध धरोहर को और मजबूत बनाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम आंतरिक सांगठनिक सद्भाव का विकास नहीं कर पाए तो यह संभव नहीं हो सकेगा। स्वस्थ सांगठनिक आचरण वाली पार्टी ही मतदाताओं के मन में विश्वास पैदा कर सकती है। सांगठनिक संचालन का उदाहरण सामूहिक नेतृत्व है, जो भाजपा को अन्य दलों से भिन्न बनाता है। अगर हम अपनी एकता को सांगठनिक उद्देश्य के रूप में विकसित नहीं कर पाए तो हम अपने उद्देश्यों के प्रति न्याय नहीं कर सकेंगे।

मित्रों नियति हमें एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी सौंपना चाहती है। आज देश में स्वतंत्रता के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकार है। जनता के पैसे की लूट और उकैती से इस सरकार ने हमारे देश को बदनाम कर दिया है। यूपीए सरकार अब बोझ बन गई है। इसने देश पर शासन करने का नैतिक अधिकार खो दिया है।

साथियों, इस पृष्ठभूमि में जब हम यहां से वापस जाएंगे तो हमें बुराई पर अच्छाई की विजय का संकल्प लेना है। आगामी सप्ताह हम विजयादशमी पर्व मनाएंगे। मैं सभी को नवरात्रि और विजयादशमी की शुभकामनाएं देता हूँ। गलत आर्थिक नीतियों और मौजूदा सरकार के कुशासन के खिलाफ अपनी लड़ाई में प्रेरक सांगठनिक गतिविधियां हमारा प्रमुख उपकरण रहेंगी। अगर किसी भी तरह से हमने इस बुनियादी तथ्य की अनदेखी की भी तो हम एक बार फिर से इस उपकरण को बाहर निकालें, इसे धारदार बनाएं और एक बार फिर से संघर्ष में जुट जाएं, ताकि अपने देशवासियों को वह सब-यानी सुशासन और स्वच्छ राजनीति उपलब्ध कराने का अपना उद्देश्य पूरा कर सकें, जिसके वे योग्य हैं।

भारत माता की जय! ■



यूपीए शासन में आधारभूत संरचनाओं का निर्माण बाधित : अरुण जेटली

Hkk रत में वर्तमान आर्थिक स्थिति बहुत ही चिंताजनक है जैसा कि हम निःसहाय होकर देख रहे हैं कि उच्च मुद्रास्फीति के कारण विकास दर काफी तेजी से कम होती जा रही है और प्रशासन के असफल होने और उच्च स्थानों पर भ्रष्टाचार के कारण कारोबार में विश्वास समाप्त हो रहा है।

देश में आर्थिक वातावरण अचानक निराशाजनक हो गया है। यूपीए ने वाम मोर्चे को यूपीए-1 के दौरान आर्थिक निर्णय लेने में पंगुता के लिए दोषी ठहराया था। तथापि, यूपीए-2 में इस प्रकार की कोई मजबूरी नहीं है। राष्ट्र को आशा थी कि सरकार नीति संबंधी निर्णय ले ताकि देश में आर्थिक गतिविधि में तेजी लाई जा सके। खेद की बात है कि भारत को अब निवेश किए जाने वाला देश नहीं माना जा रहा है। आर्थिक गतिविधि में कमी आई है। आधारभूत संरचना का निर्माण रुक गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्य क्रम और दूरसंचार क्षेत्र में घोटाले व्याप्त हैं। इनमें से कुछ विभागों में मंत्रियों के चयन पर प्रश्नचिह्न

लगा हुआ है। मुद्रास्फीति को कैसे रोका जाये, इस बारे में सरकार के पास कोई विचार नहीं है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अभी तक जो एकमात्र कदम उठाया गया है वह ब्याज दरों को बार-बार बढ़ाना है, जिसके कारण देश में क्रेडिट स्ववृद्धि हो रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में और आर्थिक गतिविधि का सृजन करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, जिससे कि सफ़लाई संबंधी समस्या को दूर किया जा सके। आर्थिक सुधारों के मामले में नीति संबंधी कोई पहल नहीं की जा रही है। तेल के मूल्यों में वृद्धि के कारण उत्पन्न स्थिति से आम आदमी की परेशानियां बढ़ गई हैं। उस पर

अक्टूबर 16-31, 2011 ○ 16



नई दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए श्री अरुण जेटली, नेता प्रतिपक्ष (राज्य सभा) द्वारा दिए गए भाषण के मुख्य बिन्दु

न केवल अन्तर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि के कारण बोझ बढ़ता है, अपितु यथा मूल्य कर ढांचे के कारण भी उस पर और अधिक बोझ पड़ता है, जबकि मूल्यों में की गई प्रत्येक वृद्धि से सरकार राजस्व भी बढ़ता है। पूरा बोझ उपभोक्ताओं पर डाल दिया गया है, जिससे आम आदमी और किसान बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। एक बेरहम सरकार समय-समय पर तेल मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि करती है और हर तिमाही के बाद ब्याज दर बढ़ा देती है। उससे अर्थ—व्यवस्था मंद पड़ जाती है। आधारभूत संरचना और नीति निर्धारण में गिरावट आई है। अधिक संख्या में भ्रष्टाचार के मामलों, विशेषकर उच्च स्थानों एवं भारी मात्रा में भ्रष्टाचार के मामलों से देश में निवेश वातावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है।

उक्त स्थिति से कुल मिलाकर यह प्रभाव हुआ कि इससे आर्थिक गतिविधि में कमी आई है, रोजगार खत्म हुए हैं, राजस्व में कमी आई है और निवेश का पलायन हुआ है। मुद्रास्फीति के उच्च स्तर से निवेश वातावरण बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इस समय हम उच्च स्फीति के कारण मंदी के कगार पर हैं। यद्यपि, इस वर्ष मॉनसून उत्साहवर्धक है और इस बार अच्छी फसल की आशा है, तथापि भारतीय किसान को अभी भी इन्फ्लेट्स की बढ़ती लागत और सामान्य खरीद मूल्यों के अपरिहार्य परिणामों का सामना करना पड़ रहा है। कर्ज के बोझ तले दबे होने के कारण अनेक किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्थिति बहुत ही निराशाजनक है। यूपीए सरकार आम आदमी के हितों की रक्षा करने के नारे से सत्ता में आई थी। इसने योजना आयोग द्वारा यह सिफारिश करवाकर इस देश के गरीबों के साथ



क्रूर मज़ाक किया है कि प्रतिदिन 32 रुपये (1 डॉलर से कम) किसी व्यक्ति को गैर-गरीब की श्रेणी में वर्गीकृत करने के लिए पर्याप्त है। गैर-गरीब होने से ऐसे व्यक्ति को अनेक क्षेत्रों में राज्य की सहायता का लाभ नहीं मिलेगा जहां पर राज सहायता देने का तात्पर्य गरीब व्यक्ति की मदद करना है। इतनी भयंकर भूल करने के बाद भी सरकार अपने इस स्टैंड से पीछे हटने के लिए किसी प्रकार का गंभीर विचार करने के लिए तैयार प्रतीत नहीं होती।

घरेलू सकल उत्पाद में कमी

जब वित्त मंत्री ने 2011 का बजट प्रस्तुत किया था, वह पूरी तरह से आशान्वित थे कि वह 2011-12 में +/-0.25 प्रतिशत के आउटसाइड बैंड के साथ 9 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त कर लेंगे। परन्तु नवीनतम प्रवृत्तियों से निराशाजनक स्थिति का पता चलता है। वर्ष 2011-12 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद विकास दर केवल 7.7 प्रतिशत है। सकल घरेलू उत्पाद में घनीभूत कमी का कारण आईआईपी (औद्योगिक उत्पादन सूचकांक) है। आईआईपी जुलाई, 2010 में 9.9 प्रतिशत के मुकाबले जुलाई, 2011 में 3.3 प्रतिशत था। अप्रैल-जुलाई 2010 में 9.7 प्रतिशत के आईआईपी विकास के मुकाबले अप्रैल-जुलाई, 2011 में यह 5.8 प्रतिशत था। औद्योगिक विकास में कमी मुख्य रूप से खनन और निर्माण क्षेत्र में है। खनन में विकास 2010-11 की पहली तिमाही में 7.4 प्रतिशत और 2009-10 की पहली तिमाही में 7.2 प्रतिशत की तुलना में 2011-12 की पहली तिमाही में केवल 1.8 प्रतिशत है। निर्माण क्षेत्र में विकास 2010-11 की पहली तिमाही में 7.7 प्रतिशत 2009-10 की पहली तिमाही में 5.4 प्रतिशत की तुलना में 2011-12 की पहली तिमाही में 1.2 प्रतिशत है। निर्माण क्षेत्र में भारी कमी के संकेत मिल रहे हैं। तिमाही में निम्नतम 4.3 प्रतिशत से बढ़कर 2009-10 की अंतिम तिमाही में अधिकतम 15.2 प्रतिशत हो गई थी, 2010-11 के दौरान धीरे-धीरे कम हो गई और 2011-12 की पहली तिमाही में विकास दर 7.2 प्रतिशत थी। इस प्रकार भारी कमी की संभावना है। ब्याज दरों के बढ़ने और मुद्रास्फीति के कारण इन्फ्लेशन की लागत बढ़ने से आज

औद्योगिक विकास पूरी तरह से अस्त-व्यस्त है।
पूंजीगत माल

यदि आईआईपी के घटकों का विश्लेषण किया जाये तो वास्तव में यह पता चलेगा कि पूंजीगत माल में विकास, जो जुलाई, 2010 में 40.7 प्रतिशत था, अब जुलाई, 2011 में 15.2 प्रतिशत है, जो नहीं के बराबर है। अप्रैल-जुलाई 2010-11 में पूंजीगत माल में विकास 23.1 प्रतिशत था, जो अप्रैल-जुलाई 2011-12 में कम होकर 7.6 प्रतिशत हो गया है। इसी तरह, मध्यवर्ती माल में विकास जुलाई 2010 में 5.8 प्रतिशत के मुकाबले जुलाई 2011 में कम हो कर 1.1 प्रतिशत हो गया जो न के बराबर है। मध्यवर्ती माल में विकास अप्रैल-जुलाई 2011-12 में कम होकर 0.8 प्रतिशत रह गया। इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, कोयला, तेल एवं गैस जैसी कोर इन्फ्रास्ट्रक्चर स्पोर्टिव इन्डस्ट्रीज़ में सीमांत कमी हुई, जो अप्रैल-जुलाई 2010-11 में 6.5 प्रतिशत थी और जो अप्रैल-जुलाई 2011-12 में कम होकर 5.8 प्रतिशत हो गई।

ऋण में कमी

मुद्रा बाजार को और कड़ा करने की प्रक्रिया अपनाई गई है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में अभी तक 4 बार रेपो दर बढ़ाई है, जो कुल मिलाकर 150 बेसिस प्वाइंट्स बैठती है। ऋण पर बढ़ती ब्याज दर से उद्योग धंधे नया निवेश करने में और अधिक कठिनाई महसूस कर रहे हैं।

राजस्व स्थिति

सरकार की राजस्व संबंधी स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। बजटीय राजस्व अनुमान (18 प्रतिशत) 9 प्रतिशत की अनुमानित घरेलू विकास दर पर और इस

देश में आर्थिक वातावरण अचानक निराशाजनक हो गया है। यूपीए ने वाम मोर्चे को यूपीए-1 के दौरान आर्थिक निर्णय लेने में पंगुता के लिए दोषी ठहराया था। तथापि, यूपीए-2 में इस प्रकार की कोई मजबूरी नहीं है। राष्ट्र को आशा थी कि सरकार नीति संबंधी निर्णय ले ताकि देश में आर्थिक गतिविधि में तेजी लाई जा सके। खेद की बात है कि भारत को अब निवेश किए जाने वाला देश नहीं माना जा रहा है। आर्थिक गतिविधि में कमी आई है। आधारभूत संरचना का निर्माण रुक गया है।

आशा पर आधारित थे कि मुद्रास्फीति लगभग 5 प्रतिशत पर नियंत्रित रहेगी। वर्तमान परिदृश्य में घरेलू विकास दर पहले ही कम होकर 7.7 प्रतिशत हो गई है और लगभग दोहरे अंकों में मुद्रास्फीति के हो जाने एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति, जहां अमेरिकी और यूरोपीय यूनियन अर्थ व्यवस्थाएं सोवरेन डेट डिफाल्ट्स/डॉउनवर्ड डेटिंग्स गिरावट दिखा रही हैं, के कारण किसी को भी इस बात पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए यदि वर्तमान वर्ष में घरेलू उत्पाद दर में और कमी हो जाती है। इससे राजस्व प्राप्तियां पूरी तरह से छिन्न-भिन्न हो



जायेंगी। राजस्व वृद्धि में भारी कमी होने के संकेत पहले से दिखाई दे रहे हैं। अप्रैल-जुलाई 2011-12 के दौरान कर राजस्व (शुद्ध) में केवल 1.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2010-11 के तदनुरूपी अवधि में कर राजस्व में हुई वृद्धि 30.7 प्रतिशत थी। इसमें भारी कमी निश्चय ही बिगड़ती अर्थ-व्यवस्था की द्योतक है।

राजकोषीय घाटे

अब हम राजकोषीय घाटे पर आते हैं। बजट में राजकोषीय घाटे को जिस स्तर (जीडीपी का 4.6 प्रतिशत) पर नियंत्रित रखने का वायदा किया गया था, वह महत्वपूर्ण है ताकि सरकारी ऋण को दीर्घकालीन में और मुद्रास्फीति को अल्पकालीन में स्थायी स्तरों पर नियंत्रित रखा जा सके। यह भारी चिंता का विषय है। वर्तमान स्थिति यह है कि 2011-12 (बजटीय अनुमान) के राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा 2010-11 की उसी अवधि में 23.8 प्रतिशत की तुलना में 55.4 प्रतिशत है। राजस्व घाटा 2010-11 की 18.1 प्रतिशत की तुलना में 2011-12 (बजटीय अनुमान) की राजस्व प्राप्तियों का 63.4 प्रतिशत है। प्राइमरी घाटा 2010-11 की उसी अवधि में 24.5 प्रतिशत की तुलना में 2011-12 (बजटीय अनुमान) की राजस्व प्राप्तियों का 111.3 प्रतिशत है, जो बहुत अधिक है। यदि आज की मीडिया रिपोर्टों को देखा जाए, तो सरकार ने बजटीय प्रावधानों की तुलना में बाजार से 53,000 करोड़ रुपये का ऋण लेने का निर्णय किया है। इसे राजकोषीय समेकीकरण कतई नहीं कहा जा सकता। वास्तव में यह राजकोषीय डिरेलमेंट है। 3जी नीलामी जैसे किसी अन्य बोनांजा होने की कोई गुंजाइश न होने से सरकार की स्थिति निराशाजनक प्रतीत होती है। यूपीए, जिसने सदैव विनिवेश के प्रति दिखावटी सहानुभूति दिखाई है, अब इस स्थिति से बाहर आने के लिए इसे अपनाते के अंतिम अवसर के रूप में देखती प्रतीत हो रही है। अंदर से पंगु हुई इस सरकार से किसी प्रकार की आशा की किरण दिखाई नहीं पड़ती जिससे कोई चमत्कारी बात हो जाए।

मुद्रास्फीति

बढ़ते राजकोषीय घाटे से, जिसे जनता से अधिकाधिक ऋण लेकर पोषित किया जा रहा है, अर्थ व्यवस्था, जो फरवरी, 2010 में लगभग 20.2 प्रतिशत की उच्च मुद्रास्फीति की पकड़ से बाहर आकर जनवरी, 2011 में 9.3 प्रतिशत हो गई थी, एक बार फिर बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण बुरी तरह से प्रभावित होने जा रही है क्योंकि मुद्रास्फीति धीरे-धीरे बढ़कर दोहरे अंकों तक पहुंचने वाली है। अगस्त, 2011 में मुद्रास्फीति 9.78 प्रतिशत बताई गई रहा, जो गत 13 महीनों

में सबसे अधिक है। जुलाई, 2011 में मुद्रास्फीति 9.22 प्रतिशत है। सतत उच्च मुद्रास्फीति उद्योग धंधों में विश्वास की कमी और निवेश में गिरावट की प्रवृत्ति का कारण है।

गिरता हुआ एफडीआई इन्फ्लो

भारत में एफडीआई में 2008 से आती गई गिरावट है। वर्ष 2008 में जो एफडीआई 42.5 बिलियन यूएस डॉलर था, वह कम होकर 2009 में 35.7 बिलियन यूएस डॉलर और 2010 में 24.6 बिलियन यूएस डॉलर हो गया। (अंकटाड रिपोर्ट) डीआईपीपी के अनुसार, भारत में शुद्ध इक्विटी एफडीआई इन्फ्लो 2008-09 में 27.33 बिलियन यूएस डॉलर से कम होकर 2009-10 में 25.83 बिलियन यूएस डॉलर और 2007-08 में 19.4 बिलियन यूएस डॉलर हो गया था। वर्तमान वर्ष में चल रही प्रवृत्ति ज्यादा उत्साहजनक नहीं है क्योंकि अप्रैल 2011 में केवल 3 बिलियन यूएस डॉलर का लो ही रिकार्ड किया गया। यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार उसी अवधि में एफडीआई इन्फ्लो में अन्य ब्रिक देशों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। एफडीआई में भारत का स्थान 8वें से गिरकर 14वां हो गया। यहां तक की इस अवधि के दौरान बंगलादेश ने भी एफडीआई में वृद्धि दर्ज की।

भारतीय उद्योगों का पलायन

दूसरी ओर, भारतीय उद्योगों द्वारा विदेशों में भारी पैमाने पर निवेश करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है क्योंकि उनका मानना है कि अन्य अर्थव्यवस्थाएं अधिक लाभप्रद हैं। विदेशों में जाने वाली एफडीआई, जो फरवरी, 2011 और फरवरी, 2010 में 20 बिलियन यूएस डॉलर के बीच थी, 2011 में लगभग दोगुनी बढ़कर 44 बिलियन यूएस डॉलर हो गई। पूंजी के बाहर जाने से रोजगार और विकास के अवसर खत्म हो गए। यूपीए स्वदेशी और विदेशी दोनों प्रकार के निवेशकों को प्रेरित करने में बुरी तरह से असफल रही है।

निर्यात

निर्यात मोर्चे पर कुछ अच्छी बात हुई है क्योंकि निर्यात में जुलाई 2010 की तुलना में जुलाई 2011 में 81.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि आयात उसी अवधि में 53.98 प्रतिशत बढ़ा। अगस्त, 2011 में निर्यात वृद्धि 44.2 प्रतिशत है। एक निष्पक्ष पर्यवेक्षक के लिए ये आंकड़े भ्रम पैदा करने वाले हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि अमेरिकी और यूरोपीयन संघ की अर्थ व्यवस्थाएं कठिन दौर से गुजर रही हैं। वे परम्परागत रूप से भारत के व्यापार पार्टनर हैं और अधिकतम निर्यात मांग में सहयोग कर रहे हैं। यदि ये अर्थव्यवस्थाएं अपेक्षित मात्रा में आयात नहीं कर रही हैं, तो प्रश्न यह उठता है कि भारत से कौन आयात कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट

शेष पृष्ठ 25 पर



कांग्रेसनीत यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार से देश शर्मसार हुआ

भारतीय जनता पार्टी की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के अंतिम दिन 1 अक्टूबर 2011 को सर्वसम्मति से 'राजनीति प्रस्ताव' पारित हुआ। इस प्रस्ताव को भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री रविशंकर प्रसाद ने रखा, जिसका अनुमोदन राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती किरण माहेश्वरी ने किया। इस प्रस्ताव में भ्रष्टाचार, महंगाई, संघीय ढांचे पर चोट और आतंकवाद को लेकर यूपीए सरकार की जमकर आलोचना की गई है। हम इसका पूरा पाठ यहां प्रकाशित कर रहे हैं :-



य खनऊ में पिछली कार्यकारिणी बैठक में भाजपा ने अपने प्रस्ताव में कहा था कि डॉ. मनमोहन सिंह स्वतंत्रता के बाद से अब तक सर्वाधिक भ्रष्ट केन्द्र सरकार के मुखिया हैं। हर गुजरते दिन से इस बात की पुष्टि होती है। भ्रष्टाचार गठबंधन की राजनीति की मजबूरियों के कारण नहीं है जैसा कि डॉ. मनमोहन सिंह बार-बार कहते हैं, बल्कि यूपीए सरकार स्वयं ही भ्रष्टाचारियों का एक गठबंधन है। भ्रष्टाचार करना और गलत काम करने वालों को दंड न देकर उसे बचाना इसके शासन की प्रमुख बात है। अभी हाल में सहयोगी दलों के लोगों, जो भ्रष्टाचार के दोषी हैं, के मामलों में अलग तरह के मापदंड अपनाए जा रहे हैं और जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं उनके लिए अलग मापदंड अपनाए जा रहे हैं।

निंदनीय खुलासों के बावजूद डॉ. मनमोहन सिंह बार-बार यह कहते हैं कि वर्तमान गृहमंत्री श्री पी. चिदम्बरम को उनका पूरा विश्वास प्राप्त है। 25 मार्च, 2011 के वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन, जिसे वर्तमान वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने स्वीकृत किया था, से तत्कालीन वित्त मंत्री के रूप में श्री चिदम्बरम की भूमिका के बारे में गंभीर प्रश्न उठाए हैं, जब यह समूचा 2जी घोटाला हुआ था और जो स्वतंत्रता के बाद भ्रष्टाचार का सबसे बदतर मामला है। अब श्री मुखर्जी ने इस बात की पुष्टि की है कि यह ज्ञापन दूर-संचार मंत्रालय के अलावा वित्त मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा मिलकर तैयार

किया गया था।

श्री चिदम्बरम के खिलाफ मामला बहुत सरल और सीधा है। तत्कालीन वित्त मंत्रालय के अति विशिष्ट अधिकारियों द्वारा बार-बार लिए गए इस स्टैंड के बावजूद कि 2001 में तय की गई दर वर्तमान में बिना कोई उचित मूल्यांकन किए 2007 में लागू की जा सकती है, उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में 15/1/2008 को प्रधानमंत्री को एक नोट भेजा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया था कि, "स्पेक्ट्रम एक दुर्लभ संसाधन है और स्पेक्ट्रम को आबंटित करने का सर्वाधिक पारदर्शी तरीका नीलामी होगा।" पहले से किए गए आबंटनों के लिए इस राय के बावजूद वित्त मंत्री ने टिप्पणी की "ऐसे मामलों में जो पहले हो गया उसे एक समाप्त चैप्टर समझा जाए।" प्रधानमंत्री ने भी राज्यसभा में 24/02/2011 को अपने वक्तव्य में इस बात की पुष्टि की कि यद्यपि वित्त मंत्री का उस समय भिन्न विचार था, जब उन्होंने 15/01/2008 को अपना नोट भेजा था। परन्तु, बाद में दूर-संचार मंत्री के साथ परामर्श करके दोनों ने स्पेक्ट्रम के मूल्यों के बारे में परस्पर एक सहमत स्टैंड लिया इसके बारे में उन्हें 04 जुलाई, 2008 को सूचित किया गया था। दिनांक 25/03/2011 के वित्त मंत्रालय के ताजा नोट, जिसे प्रधानमंत्री कार्यालय से जानकारी लेकर तैयार किया गया था, में स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि राजस्व की हानि हुई है क्योंकि वित्त मंत्रालय स्पष्ट रूप से 31 दिसम्बर, 2008 तक आबंटित किए गए लाइसेंसों के लिए वर्ष 2001 में



विद्यमान वही एन्ट्री फीस लागू करने के लिए स्पष्ट रूप से सहमत हो गया था। देश को यह जानने का अधिकार है कि श्री चिदम्बरम और उनके मंत्रालय ने अपना स्टैंड क्यों बदला। इससे यह जाहिर है कि बदले हुए स्टैंड से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा है और कुछ निजी कंपनियों को भारी आर्थिक लाभ हुआ है। वर्ष 2003 के केन्द्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार स्पेक्ट्रम के मूल्य दूर-संचार मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करके एक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निर्धारित किए जाने थे। वित्त मंत्री के रूप में श्री चिदम्बरम जनहित और सरकारी राजस्व की रक्षा करने में असफल रहे और वह भ्रष्टाचार के इस बड़े मामले में तत्कालीन दूर-संचार मंत्री श्री ए. राजा के साथ मिलीभगत में शामिल हो गए। यदि ए. राजा पर सरकारी राजस्व की हानि करने पर और कतिपय निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए मुकद्दमा चलाया जा रहा है तो श्री पी. चिदम्बरम प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का विश्वास कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जबकि उनके विरुद्ध भी यही आरोप स्पष्ट रूप से बन रहा है। क्या प्रधानमंत्री ने श्री चिदम्बरम की भूमिका के बारे में अपना होमवर्क अच्छी तरह से किया अथवा उनके पक्ष में अपना विश्वास जताने की यह मजबूरी है कि कहीं 2जी की आग की लपटें प्रधानमंत्री कार्यालय तक न पहुंचें।

हमें यह याद रखना होगा कि मंत्री समूह के दिशा निर्देशों से स्पेक्ट्रम को बाहर रखने का पूर्ण निर्णय डा0 मनमोहन सिंह द्वारा बिना किसी मंत्रिमंडल स्वीकृति के वर्ष 2006 में तत्कालीन दूरसंचार मंत्री श्री दयानिधि मारन के कहने पर एक तरफा लिया गया था। यह स्पेक्ट्रम घोटाले की शुरुआत थी। दूसरी ओर, सरकार को 35 हजार करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले लगभग 67 हजार करोड़ रुपये के राजस्व का भारी मुनाफा उस समय हुआ जब 3जी स्पेक्ट्रम की निलामी वर्ष 2010 में पारदर्शी तरीके से किया गया था। यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि श्री ए. राजा जेल में हैं और श्री दयानिधि मारन भी बहुत जल्दी वहीं जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की आपराधिकता का क्या हुआ जिन्होंने मंत्रिमंडल की अवहेलना की और स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण को

मंत्री समूह के क्षेत्रीय अधिकार से बाहर रखा जिसके कारण 2जी का भारी घोटाला होने में आसानी हुई।

प्रधानमंत्री के जोरदार समर्थन से उत्साहित सीबीआई श्री पी. चिदम्बरम के विरुद्ध पर्याप्त सबूत होने के बावजूद उनकी भूमिका की जांच करने से इनकार कर रही है। इसके विपरीत यह राजग शासनकाल के मंत्रियों श्री जसवंत सिंह, और श्री अरुण शौरी से पूछताछ की, जिनकी प्रतिष्ठा और ईमानदारी जगजाहिर है। उनसे उन लेनदेनों के बारे में पूछा जा रहा है, जो पारदर्शी थी, सार्वजनिक थी और जिनसे दूर-संचार क्षेत्र को भारी लाभ पहुंचा था। सीबीआई की साख पुनः संदेह के घेरे में है। अब श्री प्रणब मुखर्जी ने

श्री अमर सिंह यूपीए-1 में मंत्री नहीं थे और न ही उनकी तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार का हिस्सा थी। किसकी ओर से श्री अमर सिंह यूपीए-1 के पक्ष में वोट देने के लिए सांसदों को प्रलोभन दे रहे थे, यह एक स्पष्ट रूप से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कांग्रेस पार्टी और सरकार के जिन नेताओं को प्रत्यक्ष रूप से इस घोटाले से लाभ मिला था, उनकी भूमिका की जांच करने के बजाय पुलिस इसे उजागर करने वाले निर्दोष व्हिसिल ब्लोअर्स को परेशान कर रही है, जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से इस घोटाले से लाभ मिला था।

29 सितम्बर, 2011 को विभिन्न वक्तव्य दिया है कि दिनांक 25 मार्च, 2011 के नोट में उनके विचार नहीं हैं। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि यह कार्यालय ज्ञापन, जिसे आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री कार्यालय सहित अनेक विभागों के परामर्श से तैयार किया गया था, उन्होंने देखा था। इस नोट से स्पेक्ट्रम के मूल्य निर्धारण के लिए पारदर्शी प्रणाली हेतु उनके अधिकारियों के दृढ़ और निरंतर स्टैंड को अनदेखा करके सरकारी राजस्व की रक्षा न करने में श्री चिदम्बरम की भूमिका और संलिप्तता के बारे में गंभीर प्रश्न उठते हैं। हमने श्री मुखर्जी की उपस्थिति में श्री चिदम्बरम की नाटकीय टिप्पणी को भी देखा है कि वह उनके स्पष्टीकरण

को स्वीकार करते हैं। यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला नहीं है कि पार्टी अध्यक्ष के हस्तक्षेप के माध्यम से दो वरिष्ठ मंत्रियों में सुलह के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और उसके बाद यह बताया जाए कि संकट खत्म हो गया है। यह सरकारी खजाने और सरकारी राजस्व और देश को हुई हानि से जुड़ा हुआ मामला है। श्री चिदम्बरम को श्री प्रणब मुखर्जी के स्पष्टीकरण को स्वीकार करने के बारे में टिप्पणी करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है और न ही यह उनके क्षेत्राधिकार में आता है। वह स्वयं संदेह के घेरे में हैं क्योंकि वह सरकारी राजस्व के भारी नुकसान के लिए जिम्मेदार हैं।

भाजपा मांग करती है कि श्री चिदम्बरम को केन्द्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए और 2जी भ्रष्टाचार के

मामले में श्री ए. राजा की तरह उन पर भी मुकद्दमा चलाया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री द्वारा मुख्य मुद्दे से ध्यान बंटाने का प्रयास

जब भाजपा ने इस सरकार के अनेक घोटालों और भ्रष्टाचार के कारनामों का पर्दाफाश किया तो हमें अचानक पता चला है कि प्रधानमंत्री विपक्ष पर सरकार को अस्थिर बनाने और मध्यावधि चुनाव थोपने का आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा निराश होकर यह टिप्पणी की गई, जिसका उद्देश्य मुख्य मुद्दे से ध्यान बंटाना है। न तो 2जी घोटाला और न ही राष्ट्रमंडल खेल घोटाला और न ही यूपीए के अन्य घोटाले भाजपा अथवा विपक्ष के कारण हुए हैं। नोट के बदले वोट के लाभार्थी सरकार में हैं। मंत्रियों के बीच सिविल और गैर-सिविल युद्ध चल रहा है। सरकार समाप्त होने की स्थिति में है। इसे अस्थिर बनाने के लिए विपक्ष की जरूरत नहीं है।

संस्थाओं को कमजोर बनाना

भ्रष्टाचार में पूरी तरह डूबी सरकार विभिन्न संस्थानों को कमजोर बनाने और उनकी ईमानदारी से समझौता करने में जुटी हुई है। मंत्रीमंडल द्वारा लिए गये और स्वीकृत निर्णय को प्रधानमंत्री द्वारा एक तरफा बदला जा रहा है। एक सरकारी ज्ञापन के रूप में एक उचित प्राधिकृत नोट, जिसे प्रधानमंत्री कार्यालय सहित अंतर-मंत्रालीय परामर्श के बाद तैयार किया गया था जिसे वित्त मंत्री ने स्वीकृत किया था, उससे अचानक मुकर जाते हैं क्योंकि इससे श्री चिदम्बरम की आपराधिकता की ओर इशारा होता है। सीएजी और सीवीसी जैसे संस्थानों को सत्तारूढ़ पार्टी के मंत्रियों द्वारा किए जा रहे कुत्सित हमलों का पहले कभी सामना नहीं करना पड़ा जैसाकि अभी हाल में हो रहा है। सीवीसी की प्रतिष्ठा उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण ही बहाल हो पाई। तेलंगाना और मणिपुर बुरी तरह से अशांत हैं परन्तु केन्द्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से लगभग पल्ला झाड़ लिया है। श्री चिदम्बरम जैसे कांग्रेस मंत्रियों को बचाने के लिए और अन्य राजनीतिक कारणों से सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है।

नोट के बदले वोट घोटाले में सूचना देने वालों (व्हिसिल ब्लोअर्स) को निशाना बनाया गया

जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने पूर्व भाजपा सांसद श्री फगन सिंह कुलस्ते, श्री महावीर भगौरा और श्री सुधीन्द्र कुलकर्णी पर नोट के बदले वोट घोटाले में मुकद्दमा चलाये जाने की मांग की है, वह पूरी तरह से बर्बरतापूर्ण है। यह जगजाहिर है कि डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार ने यूपीए-1

के दौरान भ्रष्ट और गलत तरीकों से विश्वास मत हासिल किया था। लगभग 19 सांसदों को सरकार के पक्ष में क्रास वोटिंग करने के लिए प्रलोभन दिया गया था। व्हिसिल ब्लोअर्स भारतीय लोकतंत्र

क इस सर्वाधिक शर्मनाक प्रकरण का पर्दाफाश कर रहे थे। तीन वर्षों तक दिल्ली पुलिस ने किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की। उच्चतम न्यायालय की बार-बार प्रताड़ना के बावजूद इसने इस बात की जांच नहीं की। इससे लाभ किसको मिला? श्री अमर सिंह यूपीए-1 में मंत्री नहीं थे और न ही उनकी तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार का हिस्सा थी। किसकी ओर से श्री अमर सिंह यूपीए-1 के पक्ष में वोट देने के लिए सांसदों को प्रलोभन दे रहे थे, यह एक स्पष्ट रूप से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कांग्रेस पार्टी और सरकार के जिन नेताओं को प्रत्यक्ष रूप से इस घोटाले से लाभ मिला था, उनकी भूमिका की जांच करने के बजाय पुलिस इसे उजागर करने वाले निर्दोष व्हिसिल ब्लोअर्स को परेशान कर रही है, जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से इस घोटाले से लाभ मिला था। भाजपा पुरजोर तरीके से उनके साथ खड़ी है और समूचे देश में कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार के दोहरेपन का पर्दाफाश करने को कृतसंकल्प है।

कांग्रेस भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने में गम्भीर नहीं

जब यूपीए-2 ने अपने दो वर्ष का कार्यकाल पूरा किया तो यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी तथा प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह दोनों ने भ्रष्टाचार की बुराई के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के संकल्प की घोषणा की थी। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई और नहीं हो सकती। यदि विशेषरूप से भाजपा द्वारा एक ठोस अभियान न चलाया जाता, मीडिया सतर्क न होती तथा उच्चतम न्यायालय निगरानी न रखता तो किसी भी घोटाले में कोई कार्यवाही न हो पाती। इसके विपरीत सरकार उन लोगों के कुकृत्यों को दबाने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रही है, जो भ्रष्टाचार का अपराध करते हैं। पूर्व दूरसंचार मंत्री श्री ए राजा को प्रधानमंत्री द्वारा दो बार निर्दोष होने का प्रमाण दिया गया और इसी तरह यह कहा गया कि श्री चिदम्बरम को उनका पूर्ण विश्वास प्राप्त है।

इसके विपरीत, सरकार ने उन लोगों को उत्पीड़ित करना चाहा जिन्होंने यूपीए सरकार की गलतियों, भ्रष्टाचार तथा अन्य प्रकार की कुकृत्यों का पर्दाफाश करना चाहा और उसके लिए जवाबदेही की मांग की। जिस तरीके से शुरू में श्री अन्ना हजारे को गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल में रखा गया, जहां पर अन्य घोटालों के दोषियों को रखा गया था, और बाद में राष्ट्र में हुए शोर-शराबे के कारण उन्हें रिहा



किया गया उससे केवल इस बात की पुष्टि ही होती है। रामलीला मैदान में आधी रात को बाबा रामदेव के शांतिपूर्ण समर्थकों पर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज, जिसके कारण बाद में उनकी एक समर्थक राजबाला की मृत्यु हो गई, से इस बात का पता चलता है कि सरकार उन लोगों की आवाज को दबाने के लिए किस हद तक जा सकती है जो जवाबदेही की मांग करते हैं। भाजपा ने हमेशा उनकी बात का समर्थन किया क्योंकि वे उस निराशा और दुख की गहरी भावना को व्यक्त कर रहे थे जिसे भारत के लोग यूपीए सरकार द्वारा भारी भ्रष्टाचार करने के कारण महसूस कर रहे थे। कई अन्य मंत्रियों को उनके गलत कार्य के कारण, जिनमें राष्ट्रमंडल खेलों में दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित की मुख्य भूमिका सहित कैंग द्वारा भारी अनियमितताओं के कारण निंदा की गई थी, बड़े ही शर्मनाक तरीके से बचाव किया जा रहा है। शुंगलू कमेटी ने इससे पहले राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन में शीला दीक्षित की सरकार द्वारा किए गए गंभीर गलत कार्यों का उल्लेख किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को सरकार के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने निर्ममता से पीटा, जब वे यूपीए द्वारा किए गए भारी भ्रष्टाचार का विरोध कर रहे थे।

भाजपा एक प्रभावी लोकपाल के पक्ष में है जिसके क्षेत्राधिकार में प्रधानमंत्री का पद भी आता है। समूचे देश में इस सम्बंध में चले भारी आंदोलन को भरपूर समर्थन मिलते देखा गया। क्या यूपीए सरकार अपने पिछले रिकार्ड को ध्यान में रखते हुए एक उचित और सशक्त लोकपाल विधेयक वास्तव में लाएगी या नहीं, अब भी संदेहात्मक बनी हुई है।

पूर्व उप-प्रधानमंत्री और भाजपा संसदीय पार्टी के नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी वर्ष 2009 से यह मांग कर रहे हैं कि विदेशी बैंकों में जमा भारतीय नागरिकों के काले धन को वापस लाने के लिए पूरी ईमानदारी से प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए क्योंकि यह धन अपराध और भ्रष्टाचार से कमाया गया है। भाजपा ने इस मुद्दे को लगभग राष्ट्रीय आंदोलन बनाया है और देश में इस सम्बंध में भारी आक्रोश व्याप्त है। यहां तक की विश्व के छोटे छोटे देश भी प्रभावी कदम उठा रहे हैं। हम लगातार यह सुन रहे हैं कि काले धन के विरुद्ध बहु-अनुशासनीय समितियों का गठन किया गया है और इस सम्बंध में पंचमुखी रणनीति बनाई गई है। ये केवल खोखली घोषणाएं हैं और सरकार में काले धन का पता लगाने के लिए एक प्रभावी और सार्थक समयबद्ध कार्यक्रम लागू करने और विदेशों में उन खाताधारियों के नाम

उजागर करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं है, जो अपने अपराध से कमाएँ गये धन का लाभ उठा रहे हैं क्योंकि सरकार जानती है कि खाताधारियों का नाम बताने से केवल उसकी परेशानियां बढ़ेंगी।

भाजपा मांग करती है कि सरकार अविलंब उन खाताधारियों के नाम उजागर करने के लिए और काला धन के रूप में विदेशों में संचित अकूत धनराशि को देश में वापस लाने के लिए प्रभावी कदम उठाए।

आतंकवाद में निरंतर वृद्धि

आतंकवादियों द्वारा अपनी मर्जी से हमले जारी हैं जिनके कारण अनेक निर्दोष भारतीयों की मौत हो रही है। राजधानी के बिल्कूल बीचों-बीच आतंकवादियों ने हाल ही में उच्चतम न्यायालय के सामने निर्भय होकर हमला किया जिसमें दर्जनों निर्दोष लोग मारे गये। इससे पहले मुम्बई के झावेरी बाजार भी आतंकवादियों के हमले का निशाना बना जिसके कारण अनेक लोग मारे गये। गत दो वर्षों के दौरान हुए आतंकी हमलों में से किसी की भी ठीक प्रकार से जांच नहीं हो पाई है। आतंकवादी सीमापार से अपने संरक्षकों का पूर्ण समर्थन प्राप्त करके दिल्ली, जो भारत की राजनीतिक राजधानी है, मुम्बई जो भारत की आर्थिक राजधानी है, वाराणसी जो भारत की आध्यात्मिक राजधानी है और बैंगलूर, जो भारत की ज्ञान की राजधानी है, में अपनी आतंकी गतिविधियां जारी रखे हुए हैं। वास्तव में यह एक त्रासदी है कि अफजल गुरु को उच्चतम न्यायालय के कई वर्ष पहले आये निर्णय के बावजूद अभी तक फांसी की सजा नहीं दी गई है। इस पर दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ नियंत्रण करने के लिए प्रभावी उपाय करने की बजाय सरकार यह आभास दे रही है कि उसने इसे लगभग त्याग दिया है। अब इसे श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के प्रसिद्ध सदस्यों द्वारा एक पूर्णतः गलत और भेदभावपूर्ण साम्प्रदायिक तथा लक्षित हिंसा निवारण विधेयक, 2011 पर विचार करने की सलाह दी जा रही है। ये विधेयक पूरी तरह भेदभावपूर्ण है और भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए इसके बहुत ही खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। इसमें एक खतरनाक अवधारणा की गई है कि केवल एक बहु-संख्यक समुदाय ही सांप्रदायिक हिंसा कर सकता है और वह कभी भी उसका शिकार नहीं हो सकता। इसमें न्याय प्रदान करने की प्रणाली को भी साम्प्रदायिक विचारों के अध्याधीन किया गया है जोकि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि निहित अर्थ यह है कि अल्पसंख्यक ग्रुप को तभी न्याय मिल सकता है कि साम्प्रदायिक सौहार्द और न्याय सम्बंधी राष्ट्रीय प्राधिकरण (विधेयक में प्रस्तावित निकाय) में अल्पसंख्यक



समुदाय के सदस्यों की संख्या अधिक हो। विधेयक में केन्द्र सरकार को भारी शक्ति प्रदान की गई है कि वह लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई राज्य सरकार को बर्खास्त कर सके। भाजपा इस विधेयक का पुरजोर विरोध करती है।

गरीबी रेखा से नीचे की नई श्रेणी गरीब व्यक्ति का अपमान है

योजना आयोग, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं द्वारा उच्चतम न्यायालय के समक्ष औपचारिक रूप से दिये गये एक शपथ पत्र में बताया गया है कि गरीबी रेखा की श्रेणी में आने के लिए शहरी क्षेत्रों में 32 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 25 रुपये के अर्जन को मापदंड माना जाना चाहिए। चहुंमुखी मुद्रा स्फीति और यूपीए द्वारा पैदा की जा रही कठिनाई को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन जीवन निर्वाह की मौलिक आवश्यकताएं उपलब्ध कराने में यह मापदंड आम आदमी के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। भाजपा इस पूरी तरह से जन विरोधी बात को ढूढता से खारिज करती है और इसे वापस लेने की मांग करती है और साथ ही उसमें उचित संशोधन करने की भी मांग करती है। भाजपा मांग करती है कि गरीबी रेखा से नीचे लोगों की पहचान करने के लिए और इस संबंध में एक सही सूची बनाने के लिए एक ऐसा उचित तंत्र बनाया जाना चाहिए, जो गरीबों के हक में हो। इस संबंध में अनेक ऐसी रिपोर्टें हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के बिल्कुल विपरीत हैं। विभिन्न राज्यों में बीपीएल श्रेणी के लोगों की संख्या को सीमित करने के लिए सरकार का हठ उचित नहीं है क्योंकि इसे गरीब लोगों की वास्तविक संख्या को छुपाना माना जाएगा।

किसानों की मुसीबतें जारी

कांग्रेस नीति यूपीए सरकार किसानों की दशा के प्रति पूर्णतया उदासीन है। उर्वरकों की कमी और उनका वितरण सही ढंग से नहीं हो रहा है। केन्द्र गैर-यूपीए राज्य सरकारों को उर्वरकों के आबंटन के बारे में भेदभाव बरतती है। यहां तक की कम किया गया कोटा भी सप्लाई नहीं किया जाता, जिसके कारण बुआई के समय किसानों को भारी कठिनाई होती है। खेती-बाड़ी के काम में उपयोग आने वाले सामग्रियों

के महंगे होने के कारण खेतीबाड़ी अब और महंगी होती जा रही है। किसानों को अच्छे लाभप्रद मूल्य देने के लिए एक उचित पारदर्शी तंत्र बनाया जाना चाहिए।

गैर यूपीए राज्य सरकारों को निशाना बनाया जाना निरंतर जारी है

गैर कांग्रेसी, गैर यूपीए राज्य सरकारों को चुनिंदा तरीके से लक्ष्य बनाने का यूपीए सरकार का रिकार्ड निरंतर जारी है। यदि यह बीजेपी राज्य सरकार है तो उस पर और भी अधिक सख्त हमले किए जाते हैं। भाजपा शासित राज्यों में राज भवन कांग्रेस भवन बनते जा रहे हैं। जहां पर एक राज्यपाल सभी संवैधानिक औचित्यों का उल्लंघन करके लोकतांत्रिक ढंग से चुनी सरकार को अस्थिर बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कांग्रेस को पिछले दरवाजे से सत्ता में लाया जा सके। संघीय सिद्धान्त का निर्भयता से उल्लंघन किया जा रहा है। ताजा उदाहरण गुजरात में लोकायुक्त की नियुक्ति से सम्बंधित है। यहां पर राज्यपाल राज्य में कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी भाजपा राज्य सरकार की पूरी तरह से अन्देखी की है और उसके साथ बिना किसी सलाह मशविरा के लोकायुक्त की नियुक्ति की है। भाजपा पूरी तरह से इस असंवैधानिक कार्य की कडी निंदा करती है। और गुजरात के राज्यपाल को वापस बुलाएं

जाने की मांग करती है। बिहार राज्य में राज्यपाल कानूनी बाध्यताओं के बावजूद राज्य सरकार के साथ परामर्श किए बिना विभिन्न विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों की नियुक्ति कर रहे हैं। हालांकि न्यायालयों ने ऐसी नियुक्तियां रद्द कर दी हैं लेकिन वे फिर भी ऐसा कर रहे हैं। एक ओर कांग्रेस नीत सरकार भ्रष्ट नेताओं को संरक्षण देती है और दूसरी ओर भ्रष्ट कर्मचारियों के मामलों को फास्ट ट्रैक पर निपटाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा विशेष न्यायालय गठित किए जाने का मामला केन्द्र सरकार द्वारा लंबित रखा हुआ है।

श्री लालकृष्ण आडवाणी की जन-चेतना यात्रा

यूपीए शासन ने एक असुरक्षित और पीड़ित भारत के रूप में विरासत छोड़ी है। आम आदमी इससे पूरी तरह से प्रभावित है। अत्यावश्यक खाद्य वस्तुओं के बढ़ते मूल्यों के

शेष पृष्ठ 25 पर



यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय हितों की अनदेखी की



भारतीय जनता पार्टी की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के दूसरे दिन 1 अक्टूबर 2011 को "भारत-बांग्लादेश भूमि समझौते के संबंध में प्रस्ताव" सर्वसम्मति से पारित हुआ। इस प्रस्ताव को भाजपा सांसद श्री चंदन मित्रा ने प्रस्तुत किया जिसका अनुमोदन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती विजया चक्रवर्ती ने किया। प्रस्ताव में कहा गया है कि इस समझौते में सीमावर्ती असम और पश्चिम बंगाल के लोगों की भावनाओं और चिंता की उपेक्षा की गयी है तथा भारत और बांग्लादेश में भूखण्डों की अदला-बदली के नाम पर स्थानीय आबादी के हितों की अनदेखी की गयी है। भाजपा संकल्प करती है कि वह 6 सितम्बर 2011 के भूमि स्थानांतरण-समझौते से प्रतिकूल रूप में प्रभावित लोगों के लिए पूरी तरह संघर्ष करेगी। हम इस प्रस्ताव का पूरा पाठ यहां प्रस्तुत कर रहे हैं:

Hkk रतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की 5-6 सितम्बर, 2011 की बंगलादेश की यात्रा के दौरान भारत-बंगलादेश भूमि हस्तान्तरण समझौते के बारे में गहरी चिंता व्यक्त करती हैं। इस समझौते में सीमावर्ती असम और पश्चिम बंगाल के लोगों की भावनाओं और चिंता की उपेक्षा की गई है।

भूमि विवाद को युक्ति संगत बनाने के नाम पर और भारत तथा बंगलादेश में भूखण्डों की अदला-बदली के नाम पर स्थानीय आबादी के हितों की अनदेखी की गई है। इसके परिणामस्वरूप पूरे असम प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के अनेक हिस्सों में भारी असंतोष व्याप्त है। भाजपा ने संसद के मानसून सत्र में सरकार को चेतावनी दी थी कि वह प्रभावित लोगों से परामर्श किये बिना या संबंधित राज्यों की लोगों की भावनाओं की अनदेखी करके इस विषय में कोई निर्णय न करे।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी द्वारा राज्यसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता श्री एस.एस. आहलुवालिया के नेतृत्व में गठित संसद सदस्यों और केन्द्रीय और प्रदेश नेताओं की एक टीम ने दोनों राज्यों के प्रभावित सीमावर्ती जिलों का दौरा किया। भाजपा की टीम ने जमीनी स्थिति का अध्ययन किया और बड़ी संख्या में लोगों से मिलकर उनकी शिकायतों का संकलन किया।

भाजपा टीम ने अनुभव किया कि लोगों में व्यापक स्तर

पर भ्रम और चिंता व्याप्त है। यह समझौता उन्हें विश्वास में लेकर नहीं किया गया। लोग इस वजह से बेहद क्षुब्ध हैं कि 6 सितम्बर, 2011 के समझौते के परिणामस्वरूप भारत सरकार ने बंगलादेश द्वारा भारतीय भू-क्षेत्र के अतिक्रमण को वैधता प्रदान कर दी है और इस प्रकार गत अनेक वर्षों से पहले पूर्वी पाकिस्तान और बाद में बंगलादेश द्वारा अनेक वर्षों से गैरकानूनी तरीके से कब्जाई जमीन बंगलादेश को औपचारिक रूप से सौंप दी।

असम और पश्चिम बंगाल के अलावा त्रिपुरा और मिजोरम में भी इस समझौते को लेकर चिंता व्याप्त है। त्रिपुरा में चंदन नगर के पास की कुछ जमीन हस्तांतरित की जानी है, जिसे लेकर स्थानीय भारतीय निवासियों में भारी चिंता व्याप्त है।

यद्यपि सीमा के पुनर्रखन से पूर्व भारत और बंगलादेश के अधिकारियों में लगभग 1500 सर्वे मानचित्रों का आदान प्रदान किया गया लेकिन जनता को इन मानचित्रों की कोई जानकारी नहीं दी गई। सीमा पर तैनात भारतीय सुरक्षा सेनाओं को भी इस विषय में अंधेरे में रखा गया है। इस समझौते के कारण जिन भारतीय किसानों को अपनी पुश्तैनी जमीन गंवानी पड़ रही है, उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि गंवाई जोन वाली जमीन के बदले उन्हें भारतीय क्षेत्र में जमीन दी जायेगी या मुआवजा दिया जायेगा। वे चिंतित हैं कि कहीं वे अपने ही देश में शरणार्थी न बन जायें।

भाजपा मांग करती है कि सरकार संसद के समक्ष भूमि

हस्तांतरण समझौते का पूरा ब्यौरा और संबंधित सर्वे मानचित्र रखे। हमारी पार्टी संसद के शीतकालीन सत्र में इस समझौते पर विस्तृत चर्चा की मांग करती है, पेशतर इसके कि सरकार भारतीय भूक्षेत्र को हस्तांतरित करने का कदम उठाये।

यद्यपि भाजपा बंगलादेश से अपने संबंधों को सुधारने के पक्ष में है और वह बंगलादेश की भूमि से आतंकी गतिविधियां चलाने वाले अलगाववादी तत्वों पर अंकुश लगाने की ढाका सरकार की प्रशंसा करती है, लेकिन वह भारतीय नागरिकों की आजीविका और संपत्ति की कीमत पर यह नहीं कर सकती।

भाजपा का मत है कि भारत के खिलाफ गैरकानूनी बंगलादेशी अतिक्रमण के रूप में होने वाले जनसांख्यिकीय आक्रमण के परिणाम स्वरूप असम और पश्चिम बंगाल के अनेक क्षेत्रों की अस्मिता, संस्कृति और सामाजिक एकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। राष्ट्र के हितों के साथ और समझौता बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। भाजपा संकल्प करती है कि वह 6 सितम्बर, 2011 के भूमि स्थानांतरण समझौते से प्रतिकूल रूप में प्रभावित लोगों के लिए पूरी तरह संघर्ष करेगी। भाजपा मांग करती है कि सरकार संसद के सामने अपनी सफाई पेश करे और अपने को निर्दोष साबित करे। ■

पृष्ठ 18 का शेष...

बताती हैं कि आईएमएफ के हाल के एक अध्ययन से पता चलता है कि भारत से आयात, जैसाकि अन्य देशों द्वारा बताया गया है, में इन निर्यात आंकड़ों को शामिल नहीं किया गया है। ये रिपोर्टें भी मिली हैं कि विदेशों में जमा काले धन को अधिक बिलिंग के माध्यम से निर्यात से होने वाली आय के रूप में अवैध रूप से वापस लाया जा रहा है। परन्तु यदि सरकार सच्चाई जानने और त्रुटियों को दूर करने के लिए गंभीर है, तो इसे इन आरोपों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए बजाय इसके कि वह इस बात के लिए खुश हो जो अस्तित्व में है ही नहीं। यूपीए द्वारा आधारभूत संरचना क्षेत्र में पीपीपी मॉडल के माध्यम से निवेश किए जाने की बड़ी-बड़ी बातें की जा रही हैं। यूपीए के 7 वर्षों के शासनकाल में ऐसी कोई भी प्रमुख उपलब्धि नहीं हुई, जिसका उल्लेख किया जाए। सारांश में, भारत का वर्तमान आर्थिक परिदृश्य ऐसा है जहां उच्च मुद्रास्फीति सहित विकास में स्थिरता है। क्या इसे स्थिरता कहा जा सकता है, यह एक तकनीकी मुद्दा है, परन्तु इस प्रकार के सभी संकेत यहां मौजूद हैं। मूल्यों में चहुंमुखी वृद्धि के साथ विकास में कमी आई है। यह एक ढांचा संबंधी समस्या है, जो तेजी से परिवर्तित हो रहे परिदृश्य को ध्यान में रखकर सही नीति निर्धारण करने में यूपीए की अक्षमता के कारण पैदा हुई है। वे सुधार हुए ही नहीं, जो होने थे। यहां पर लंबे समय से विद्यमान पूंजीवाद, भ्रष्टाचार और यूपीए के भीतर इसके प्रति बढ़ती उसकी सहिष्णुता दिखाई देती है। अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री का असहाय होना प्रतीत होता है। ■

पृष्ठ 23 का शेष...

साथ मुद्रास्फीति और एक सामान्य मंदी से उनका जीवन दुखमय हो गया है, सतत आतंकी हमलों से वे असुरक्षित हो गए हैं। सभी ओर व्याप्त भ्रष्टाचार, जिसे यूपीए सरकार का संरक्षण प्राप्त है, से वे पूरी तरह से आक्रोशित हैं। केन्द्र सरकार में उन लोगों के कहने पर भारी मात्रा में सरकारी धन की बार-बार लूट से देश में दुख और निराशा की गहरी भावना है, जो उसकी रक्षा करने के लिए कृतसंकल्प थे। यूपीए के अधीन सुराज खत्म हो गया है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार के पास कोई इच्छाशक्ति नहीं है। वरिष्ठ स्तर के अनेक कांग्रेस नेता अपने विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्रवाई होने के डर के बिना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने और उसको संरक्षण प्रदान करने में पूरी तरह से लिप्त हैं। निराशा भरी इस स्थिति में श्री लालकृष्ण आडवाणी ने सम्पूर्ण देश में एक जन चेतना यात्रा करने का निर्णय लिया है ताकि देश के लोगों को भ्रष्टाचार के कैंसर के विरुद्ध और सुराज की इच्छा के प्रति जागरूक किया जा सके। भारतीय राजनीति के शिखर पुरुषों में एक श्री लालकृष्ण आडवाणी की स्वच्छ छवि, राष्ट्र के प्रति निष्ठा और निजी ईमानदारी असंदिग्ध है। भाजपा पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, समर्थकों एवं आम जनता का आह्वान करती है कि सब एकजुट होकर आगे आये और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन-मन के आक्रोश को एक निर्णायक परिणति की ओर ले जाने के लिए आडवाणी जी के नेतृत्व में प्रारंभ इस जन-चेतना अभियान को गति और शक्ति प्रदान करने में सकारात्मक एवं सक्रिय योगदान दें। पार्टी देश के लोगों का आह्वान करती है कि जहां भी यह यात्रा जाए वे उसमें भारी संख्या में शामिल हों और कांग्रेस नीत यूपीए सरकार ने जिस तरीके से भारी भ्रष्टाचार और कुशासन से भारत को शर्मसार किया है उसकी निंदा करें। भाजपा को पूरा विश्वास है कि देश के लोग, परिपक्व है और जो मन से देश का भला चाहते हैं, इस अवसर का लाभ उठाएंगे और स्वच्छ राजनीति और सुराज के लिए एक बार फिर भारत को जागृत करने का वातावरण पैदा करेंगे। ■

सु-शासन और स्वच्छ राजनीति के लिए जनचेतना यात्रा



सु-शासन की शक्ति, साफ-सुथरी राजनीति!

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में 11 अक्टूबर 2011 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली सिताब दियारा से सु-शासन और स्वच्छ राजनीति के लिए एक जनचेतना यात्रा का आयोजन किया गया है। यात्रा के विस्तृत कार्यक्रम की रूपरेखा को 29 सितम्बर 2011 को श्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में अंतिम रूप दिया गया। इस बैठक में पार्टी के प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरी पार्टी जुट गई है।

पार्टी अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने पार्टी महासचिव श्री अनंत कुमार को इस यात्रा का मुख्य संयोजक नियुक्त किया है। सह-संयोजक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री रविशंकर प्रसाद और राष्ट्रीय सचिव सर्व श्री मुरलीधर राव तथा श्याम जाजू रहेंगे।

लोकतांत्रिक राजनीति को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने तथा देश में जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील, जवाबदेह, तथा पारदर्शी तथा सु-राज स्थापित करने के लिए जनचेतना को जगाना – यह इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। कानून का शासन, प्रशासन में पारदर्शिता और लोगों की सहभागिता

इस यात्रा के मुख्य सूत्र है। यूपीए शासन में गंभीर घोटालों के चलते देश के खजाने की बेहताशा खुली लूट से पूरा देश सन्न है।

कांग्रेस सरकार के भ्रष्ट कारनामों के बारे में व्यापक लोक शिक्षा के माध्यम से जनजागृति करने पर इस यात्रा में बल दिया जाएगा। मगर यह यात्रा व्यापक व्यवस्थागत-सुधारों से जुड़े मुद्दों को भी उजागर करेगी। प्रशासनिक सुधार,

कांग्रेस सरकार के भ्रष्ट कारनामों के बारे में व्यापक लोक शिक्षा के माध्यम से जनजागृति करने पर इस यात्रा में बल दिया जाएगा। मगर यह यात्रा व्यापक व्यवस्थागत-सुधारों से जुड़े मुद्दों को भी उजागर करेगी।

चुनाव-सुधार, न्यायिक-सुधार और राजनीतिक-सुधार इन चार महत्वपूर्ण सुधारों के विषय में लोगों के बीच जाकर एक बहस निर्माण करना इस यात्रा की मुख्य भूमिका रहेगी।

साथ ही, सु-शासन और साफ-राजनीति के विषय में भाजपा की सोच तथा पार्टी के बहु आयामी

प्रयासों के बारे में भी इस यात्रा के दौरान लोगों को अवगत कराया जाएगा।

यात्रा के दौरान जनसभाएं तो होगी ही, मगर साथ ही -

- ▶ सामाजिक संस्थाओं के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन,
- ▶ इंटरनेट के माध्यम से जनजागरण करने वाले ई-कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा बैठकें तथा भाजपा के जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन इत्यादि कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। ■

“यूपीए सरकार में नेतृत्व का गंभीर संकट”

Hkk रत वापस आने पर प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा दिए गए वक्तव्य से जमीनी सच्चाई से उनकी अनभिज्ञता का पता चलता है। राष्ट्र प्रधानमंत्री द्वारा हर बात नकारने से अचंभित है।

गृहमंत्री को प्रधानमंत्री का विश्वास प्राप्त

प्रधानमंत्री ने गत कुछ दिनों से सदैव यह दावा किया है कि सार्वजनिक हो रहे निंदनीय खुलासों के बावजूद गृहमंत्री श्री पी. चिदम्बरम को उनका पूरा विश्वास प्राप्त है। प्रधानमंत्री का श्री चिदम्बरम को समर्थन न तो तथ्यों पर आधारित बताया जा सकता है और न ही 2जी के विवादों के मैरिट पर आधारित बताया जा सकता है। यदि ऐसा है तो प्रधानमंत्री को कम से कम देश को यह बताना होगा कि क्या वित्त मंत्री के रूप में श्री चिदम्बरम के स्टैंड में परिवर्तन के बारे

में अपनी तसल्ली की है, जिसमें उनके मंत्रालय ने शुरू में स्पेक्ट्रम के आबंटन के लिए वर्तमान मूल्य फार्मूले की सिफारिश की थी, परन्तु वर्ष 2008 में स्पेक्ट्रम को 2001 के मूल्य पर आबंटित करने के लिए श्री ए. राजा का समर्थन किया। यह बात तो सत्य है कि श्री चिदम्बरम और उनके मंत्रालय ने अपने रवैये को बदला था। यह बात भी सत्य है कि इस बदले हुए रवैये से सरकारी खजाने को नुकसान हुआ और कतिपय निजी कंपनियों को भारी मुनाफा हुआ।

15 जनवरी, 2008 को श्री चिदम्बरम के नोट में यह तर्क दिया गया है कि स्पेक्ट्रम के आबंटन के लिए नीलामी ही सही तरीका है, परन्तु यह मामला दूरसंचार मंत्री द्वारा कतिपय लाइसेंसधारियों को रियायती मूल्य पर आबंटन करने से खत्म हुआ। यदि

की आपराधिकता संबंधी तर्क को बल मिलता है। यह बात स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री श्री चिदम्बरम और उन लोगों के लिए चिंतित है, जिन्हें सरकारी खजाने की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। परन्तु, उनकी गलतियों के कारण भारत सरकार को भारी नुकसान हुआ है।

सीबीआई का भेदभावपूर्ण रवैया

केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने राजग सरकार के मंत्रियों श्री जसवंत सिंह और श्री अरुण शौरी से पूछताछ की है। श्री जसवंत सिंह और श्री शौरी दोनों अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। उनसे उन लेन-देन के बारे में पूछताछ की जा रही है, जो पारदर्शी और पूरी तरह सार्वजनिक थे और जिनसे दूरसंचार क्षेत्र को भारी लाभ हुआ। सीबीआई श्री चिदम्बरम के लिए

एक अलग मापदंड अपना रही है, जबकि उनके विरुद्ध पर्याप्त प्रमाण मौजूद हैं। एक जांच एजेंसी के रूप में सीबीआई की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में है।

प्रधानमंत्री का मानना है कि उनके मंत्रिमंडल में कोई मतभेद नहीं है

प्रधानमंत्री द्वारा बड़े जोरदार शब्दों में कहना कि उनके मंत्रिमंडल में कोई भेदभाव नहीं है, गत कुछ दिनों की घटनाओं को देखते हुए हमें उस पर अचंभा होता है। संसद के गत सत्र में



श्रीमती सुषमा स्वराज, नेता प्रतिपक्ष (लोकसभा) व श्री अरुण जेटली, नेता प्रतिपक्ष (राज्यसभा) द्वारा 28 सितम्बर, 2011 को जारी प्रेस वक्तव्य

कतिपय निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के आरोप में अन्य व्यक्तियों के साथ श्री ए. राजा पर मुकद्दमा चलाया जा रहा है तो श्री पी. चिदम्बरम किस प्रकार से प्रधानमंत्री का विश्वास प्राप्त कर रहे हैं, जबकि उनके विरुद्ध भी यही आरोप स्पष्ट रूप से बनता है। दिनांक 25/03/2011 के वित्त मंत्रालय के नोट से राष्ट्र को यह पता चला है कि वर्तमान वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम की कार्यवाही के बारे में क्या सोचते हैं। इससे श्री पी. चिदम्बरम

सरकार में दरार पड़ना प्रतीत हो गया था। श्री अन्ना हजारे के अनशन से उत्पन्न स्थिति का समाधान कर लेने के बाद वरिष्ठ मंत्रियों के आपस में बिलकुल विपरीत दृष्टिकोण थे। वित्त मंत्री ने एक प्राइवेट एजेंसी के द्वारा अपने कार्यालय में हो रही जासूसी को यह आशंका जताते हुए समाप्त करवाया कि कुछ एजेंसियां उनके कार्यालय में जासूसी कर रही हैं। वित्त मंत्रालय के उस नोट, जो वित्त मंत्री ने 25/03/11 की अपनी स्वीकृति के बाद भेजा था, में निर्णायक रूप से श्री पी. चिदम्बरम की भूमिका की ओर इशारा किया गया है। स्पष्ट रूप से पी. चिदम्बरम नाराज हैं। मंत्रियों के बीच अविश्वास का मामला मीडिया और जनता के बीच आ गया है। प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य पर कोई विश्वास नहीं कर रहा कि मंत्रिमंडल में कोई मतभेद नहीं है।

यह कहना कि विपक्ष सरकार को अस्थिर बनाने का प्रयास कर रहा है

विपक्ष के पास सरकार को अस्थिर बनाने के लिए वांछित संख्या में सदस्य नहीं है। हमने कोई अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं किया है। सरकार ही अपनी वैधता नष्ट कर रही है। 2जी घोटाला विपक्ष द्वारा नहीं बनाया गया है। राष्ट्रमंडल खेलों में भ्रष्टाचार विपक्ष के कारण नहीं हुआ है। वोट के बदले नोट के लाभार्थी सरकार में ही हैं। आर्थिक निर्णयों संबंधी पंगुता सरकार के कारण ही है। हम आर्थिक मंदी और उच्च मुद्रास्फीति की ओर बढ़ रहे हैं।

आतंकी हमले पुनः चालू हो गए हैं। सरकार में नेतृत्व का गंभीर संकट है। बाबा रामदेव और श्री अन्ना हजारे के आंदोलनों से गलत ढंग से निपटने के लिए सरकार की साख गिरी है। यह सरकार खत्म होने के कगार पर है। विपक्ष द्वारा इसे अस्थिर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ■

भागवत झा आजाद नहीं रहे

वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भागवत झा आजाद का निधन 4 अक्टूबर को नई दिल्ली में हो गया। वे 89 वर्ष के थे। श्री आजाद का इलाज गत कुछ दिनों से एम्स में चल रहा था। श्री आजाद कुल छह बार बिहार के भागलपुर जिले से सांसद रह चुके थे। वे पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी और लोकसभा सांसद कीर्ति झा आजाद के पिता थे।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी का शोक संदेश

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ राजनीतिज्ञ श्री भागवत झा आजाद ने प्रशासन और राजनीति में अपनी शैली से एक विशिष्ट छाप छोड़ी। वे लोकसभा में भागलपुर का प्रतिनिधित्व करते रहे। एक जनप्रतिनिधि के रूप में उन्होंने लोगों के दिलों में अपना अलग स्थान बनाया। आधुनिक बिहार बनाने वाले राजनीतिज्ञों में से वे एक थे। उनके निधन से सार्वजनिक जीवन में अपूरणीय क्षति हुई है। मैं प्रभु से उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने तथा उनके परिजनों को यह दुःख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना करता हूँ।

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं मुख्य प्रवक्ता, सांसद श्री रवि शंकर प्रसाद का शोक संदेश

श्री भागवत झा आजाद बहुत ही कर्मठ व ईमानदार लोकप्रिय नेता थे। अपनी लगन और परिश्रम के द्वारा उन्होंने एक जुझारू नेता के रूप में राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान बनाई थी। भ्रष्टाचार मुक्त स्वच्छ राजनीति के वे सदैव पक्षधर रहे। भ्रष्टाचार के विरुद्ध उन्होंने सदैव जन-जागरण किया। उनके निधन से भारतीय राजनीति का एक उज्ज्वल नक्षत्र अस्त हो गया है। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वह दिवंगत आत्मा को शांति और उनके परिजनों को यह दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें। ■

~~~~~@~~~~~

## हरि प्रसाद शाह का निधन

पिछले दिनों बिहार के पंचायत राज मंत्री श्री हरि प्रसाद शाह का निधन हो गया। 74 वर्षीय श्री शाह बिहार के प्रसिद्ध समाजवादी नेता थे। मिथिलांचल क्षेत्र से वे कई बार विधायक रहे।

### भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री नितिन गडकरी का शोक संदेश

श्री हरि प्रसाद शाह एक कर्मठ व ईमानदार लोकप्रिय नेता थे। अपनी लगन और परिश्रम के द्वारा उन्होंने एक जुझारू नेता के रूप में राजनीति में अपनी पहचान बनाई थी। उनके निधन से बिहार की राजनीति का एक स्तम्भ गिर गया है। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वह दिवंगत आत्मा को शांति और उनके परिजनों को यह दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें। ■



**X**त् सप्ताह नई दिल्ली में सम्पन्न भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समापन सत्र में मैंने प्रधानमंत्री की इन टिप्पणियों का हवाला दिया कि विपक्ष यूपीए सरकार को गिराने के लिए उतावला हो रहा है ताकि शीघ्र चुनाव कराए जा सकें। मैंने कहा कि आज देश में न केवल मीडिया अपितु लोगों के बीच यह सर्वसम्मत मत बना हुआ है कि यूपीए सरकार अवांछनीय गड़बड़ी में फंसी हुई है। यह तथ्य भी सर्वविदित है कि यह गड़बड़ी कांग्रेस की अपनी बनाई हुई है। मैंने यूपीए सरकार को 'आत्महत्या पर उतारू' रूप में वर्णित किया।

भाजपा के गठन से पहले के 6-7 महीनों की अवधि को मैं कभी नहीं भुला सकता। उससे पूर्व हम जनता पार्टी के घटक थे। उस समय मैंने अपनी स्वयं की पार्टी के बारे में सार्वजनिक रूप से कहा था कि हम आत्महत्या पर उतारू हैं।

उन दिनों के लिखे गए एक लेख में मैंने स्कैंडिनवियन में चूहे जैसे पाए जाने वाले एक जीव लेमिंग का उल्लेख किया था। मैंने लिखा था कि केवल मनुष्यों में ही आत्महत्या की प्रवृत्ति पाई जाती है। लेकिन लेमिंग अपने आप में अनोखा प्राणी है।

बगैर किसी तर्क या कारण के,

बड़ी मात्रा में लेमिंग समुद्र की ओर मार्च शुरू करते हैं। कुछ तैरकर बच जाते हैं। अधिकतर मर जाते हैं। लेमिंग की सामूहिक आत्महत्याओं से जीव विज्ञानियों में भी कौतुहल है। तब मैंने लिखा था कि जनता पार्टी लगता है "लेमिंग काम्प्लेक्स से ग्रसित है"। कोई भी यही बात आज यूपीए सरकार के बारे में कह सकता है।

“

दिसम्बर, 2001 में विधि आयोग ने अपनी 179वीं रिपोर्ट में भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले व्हिसल-ब्लोअरों को संरक्षण देने हेतु कानून बनाने की जोरदार सिफारिश की थी।

113 पृष्ठीय रिपोर्ट की शुरुआत में आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश बी.पी. जीवन रेड्डी का तत्कालीन विधि मंत्री अरुण जेटली को लिखा गया पत्र है जिसमें प्रधानमंत्री वाजपेयी को उकृत करते हुए कहा गया कि भ्रष्टाचार के प्रति देश का रुख 'जीरो टॉलरेन्स' होना चाहिए। रिपोर्ट के अन्य अध्यायों में ब्रिटेन, अमेरिका, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड में व्हिसल-ब्लोअरों को दिए गए संवैधानिक संरक्षणों का वर्णन किया गया है।

विधि आयोग की रिपोर्ट के आधार पर मनमोहन सिंह कैबिनेट ने व्हिसल-ब्लोअरों को दिए संरक्षण देने

वाले विधेयक को स्वीकृति दी और 2010 में इसे लोकसभा में तत्कालीन मंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने प्रस्तुत किया। वर्तमान में यह विधेयक संसद की स्थायी समिति के पास विचाराधीन है।

यह विधेयक अभी कानून नहीं बना है। लेकिन चूंकि कैबिनेट ने इसे अपनी स्वी.ति दी है, तो सरकार को इसके मुख्य तत्व के प्रति अपने को प्रतिबद्ध महसूस करना चाहिए।

पिछले सप्ताह अरुण जेटली के साथ तिहाड़ जेल में वर्षों से मेरे निकट सहयोगी रहे सुधीन्द्र कुलकर्णी और दो पूर्व पार्टी सांसदों कुलस्ते और भगोरा से मिला जिन्होंने सन् 2008 में वाम पंथियों द्वारा कांग्रेस से समर्थन वापस लेने के बाद कांग्रेस के समर्थन में घूस देकर सांसदों को वोट देने के लिए तैयार किया गया जिससे यूपीए-2 विश्वास मत प्राप्त कर सका। वाम मोर्चे ने भारत-अमेरिका परमाणु सौदे के विरोध में कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। अशोक अर्गल सहित तीन भाजपा सांसदों को यूपीए द्वारा अपने पक्ष में वोट देने के लिए तीन करोड़ रुपये प्रति सांसद की पेशकश की गई और एक करोड़ रुपया एडवांस भी दिया गया।

दि हिन्दू ने विकीलीक्स की एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें दर्शाया

गया था कि मनमोहन सरकार न केवल सांसदों को घूस देने के मामले में शामिल थी अपितु इसे अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों के सामने इस कुत्सित योजना को बताने में भी कोई शर्म नहीं आई क्योंकि ये उन्हें आश्चर्य करना चाहते थे कि यूपीए सरकार गिरने वाली नहीं है और भारत-अमेरिकी परमाणु सौदा स्वीकृत होने में कोई अड़चन नहीं आएगी।

वस्तुतः यह देखकर आश्चर्य होता है कि इन दिनों सत्तारूढ़ दल अपनी पूरी शक्ति भ्रष्ट मंत्रियों के बचाव करने में लगा रहा है लेकिन व्हिसल-ब्लोअरों को सीखचों के पीछे भेजने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा।

”

दुनियाभर के देशों में भ्रष्टाचार के स्तर को मापने का काम करने वाला एक संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल प्रत्येक देश के लिए करप्शन प्रिसेप्शन इंडेक्स (CPI) तैयार करता है और प्रत्येक वर्ष एक विशद सूची प्रकाशित करता है। 'करप्शन प्रिसेप्शन इंडेक्स' शून्य से दस के स्केल पर देशों को स्कोर देते हैं, शून्य का अर्थ होता है सर्वाधिक भ्रष्टाचार और दस भ्रष्टाचार का न्यूनतम स्तर दर्शाता है।

सन् 2010 को प्रकाशित सूची भारत का स्कोर 3.3 दर्शाती है और 178 देशों में 87वें निचले दर्जे पर।

डेनमार्क, सिंगापुर और न्यूजीलैण्ड — इन तीनों देशों का स्कोर 9.3 है और 2010 की 178 देशों की सूची में पहले स्थान पर हैं।

2.3 स्कोर के साथ पाकिस्तान सूची में 143वें स्थान पर है। अफगानिस्तान, बर्मा और सोमालिया अंतिम तीन — 176, 177 व 178 क्रम पर हैं।

### (पश्चलेख)टेलपीस

30 सितम्बर को कांग्रेस अध्यक्ष ने 2जी विवाद पर गुल्मगुत्था दो वरिष्ठ मंत्रियों के बीच सुलह कराई। उस राज जब मैंने टीवी खोला तो देखा कि सलमान खुशी से उछल रहे थे और चिल्ला रहे थे 'सब ठीक है (All is well)' —जोकि एक लोकप्रिय फिल्म की 'पंचलाइन' थी। वहां मौजूद मीडियाकर्मियों में से एक ने मुझे बाद में बताया: मीडियावालों में से एक आवाज यह पूछते हुए सुनी गई : सलमान साहब, क्या आप 'थ्री इडियट्स (Three Idiots)' के नाम बताएंगे? ■

## यूपीए को सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं : राजनाथ सिंह

लखनऊ, 29 सितम्बर(हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाले में घिरी कांग्रेसनीत संग्रम सरकार से इस्तीफा देकर मध्यावधि चुनाव कराने की मांग की है। श्री सिंह ने आज हुए पार्टी के सामाजिक न्याय सम्मेलन को सम्बोधित करने के बाद पत्रकारों से कहा “ 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में पूरी संग्रम सरकार कटघरे में खड़ी है और उसे सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं रह गया है। उन्होंने कहा, “यूपीए सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए और नयी सरकार के लिए मध्यावधि चुनाव कराये जाने चाहिए।” श्री सिंह ने यह भी कहा कि 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले में तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम को भी सीबीआई के जांच दायरे में लाया जाना चाहिए। श्री सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार के विरोध में देश में जागरूकता पैदा करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे बधाई के पात्र है और भाजपा भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में उनके साथ है। इससे पूर्व पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के लोगों को उनका अधिकार दिलाने के लिए आयोजित पार्टी के सामाजिक न्याय सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए भी राजनाथ सिंह ने केन्द्र में संग्रम सरकार की अगुवाई कर रही कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लेते हुए कहा “ लोगों की गरीबी और बेरोजगारी उनकी बदकिस्मती की वजह से नहीं है, बल्कि इसके लिए वे जिम्मेदार हैं जो देश में लम्बे समय तक राज करते आये हैं।”

## उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार की राजनीति से मुक्त करेगी भाजपा : उमा भारती

लखनऊ 03 अक्टूबर (हि.स.)। समाजिक न्याय महासम्मेलन में उत्तर प्रदेश भाजपा प्रभारी सुश्री उमा भारती ने महात्मा गांधी तथा लालबहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि सपा और बसपा ने उत्तम प्रदेश में ऐसे-ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में जगह दी है जो प्रदेश के राजनैतिक परिवेश को दूषित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बसपा और सपा दोनों आज तक एक अच्छी सरकार नहीं दे सके। इनकी पार्टी में ऐसे भ्रष्ट लोग हैं, जो भ्रष्टाचार खत्म करने के बजाए उसे और बढ़ा रहे हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में ला कर देश की तस्वीर बदलने में सहयोग करें। सुश्री भारती ने कहा कि हम सत्ता की राजनीति नहीं करते, बल्कि पराक्रम की राजनीति करते हैं जिसमें लोगों के जोश और हमारे होश से उत्तम प्रदेश को भ्रष्टाचार की राजनीति व अपराध से मुक्त किया जायेगा। तैलिक समाज के नेता राम नारायण साहू ने भी सभा को सम्बोधित किया। ■